



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 11 अक्टूबर, 2005/19 आश्विन, 1927

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, शिमला

आदेश

शिमला, 6 अक्टूबर, 2005

कार्यालय आदेश (414).—हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात “उक्त विनियम” कहा गया है) 30 मार्च, 2005 को लागू हुए ;

और उक्त विनियमों के विनियम 2 के खण्ड (ख) सहित पठित विनियम 5 के अन्तर्गत सारणी यह अपेक्षा करती है कि परिसर का स्वामी या अधिकारी, जो विद्युत प्रदाय के लिये वितरण अनुज्ञापतिधारी को आवेदन करता है, उसे विद्युत प्रदाय की जाने वाली विद्युत के लिये संयोजित भार/संवेदित मांग के प्रति किलोवाट/के. वी. ए. अथवा उसके भाग पर सपाट दरों पर प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप संदत्त करेगा ;

और यह कि आवेदक किन मामलों में संयोजित भार या संवेदित मांग के आधार पर प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप संदत्त करेगा, सुनिश्चित करने में कठिनाई उद्भूत हुई है;

अब, अतः आयोग, उक्त विनियमों के विनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयोजित भार या संवेदित मांग के आधार पर प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप करने के सम्बन्ध में कठिनाईयों को दूर करने के लिये, जो अधिनियम तथा उक्त विनियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, निम्नलिखित आदेश करता है :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) [कठिनाईयों को दूर करना] आदेश, 2005 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

2. प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप.—प्रारम्भिक प्रतिभूति निक्षेप, प्रति किलोवाट/के. वी. ए. अथवा उसके भाग पर,—

(क) यहां टैरिफ एकल बिन्दु, जैसे कि किलोवाट/के. वी. ए. आधारित हो, वहां संयोजित भार के आधार पर देय होगा; तथा

(ख) यहां टैरिफ दो बिन्दुओं, जैसे कि मांग तथा ऊर्जा प्रभार आधारित हो, वहां संवेदित मांग के आधार पर देय होगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
SHIMLA**

ORDER

Shimla, the 6th October, 2005

S.O.(414).---Whereas the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) Regulations, 2005 (hereinafter referred to as "the said regulations") came into force on the 30th March, 2005 ;

And whereas the table under regulation 5, read with clause (b) of regulation 2, of the said regulations provides that the owner or the occupier of any premises, who makes an application to the distribution licensee for supply of electricity shall pay initial security deposit towards the electricity to be supplied to him at flat rates per KW/KVA or fraction thereof of connected load/contract demand ;

And whereas difficulty has arisen in ascertaining the circumstances in which the applicant should pay the security deposit on the basis of connected load or on the basis of contract demand ;

Now, therefore, the Commission in exercise of the powers conferred on it by regulation 10 of the said regulations, hereby makes this order in respect of payment of initial security deposit on connected load or contract demand, not in consistent with the provisions of the Electricity Act, 2003 and the said regulations, to remove the difficulty namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Security Deposit) [Removal of Difficulties] (First) Order, 2005.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Initial security deposit.—The initial security deposit per KW/KVA or fraction thereof.—

(a) wherever the tariff is single part *i. e.* KWH, shall be on the

basis of the connected load ; and

- (b) wherever the tariff is two part on demand and energy charge, shall be on the basis of the contract demand.

शिमला, 30 सितम्बर, 2005

अधिसूचनाएं

संख्या: एच0 पी0 इ0 आर0 सी/407.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003, (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) सहित पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस द्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या एच.पी.इ.आर.सी/381 दिनांक 10-6-2004 द्वारा बनाये तथा आयोग की अधिसूचना संख्या.एच.पी.इ.आर.सी/381 दिनांक 22-2-2005 द्वारा संशोधित किए गए हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसीटी रेगुलेटरी कमीशन (जनरल कण्डीशनज आफ ट्रेडिंग लाईसेंस) रेगुलेशनज, 2004, किन्हीं कारणों से जिनका हिन्दी पाठ प्रकाशित नहीं हो पाया है, का निम्न हिन्दी पाठ प्रकाशित करता है:—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (व्यापारिक अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम 10 जून, 2004 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.— इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) “लेखा विवरण” से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में दिए गए विवरण के अनुसार अनुज्ञप्त कारोबार के लेखा विवरण, अभिप्रेत हैं जिसमें लाभ—हानि लेखा, तुलन—पत्र और संसाधनों का तथा निधियों की प्रायोज्यता का टिप्पणियों सहित

*विवरण तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निदेशित अन्य ऐसे विवरण व व्यौरे समाविष्ट होंगे। यदि व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार के अतिरिक्त किसी अन्य कारोबार अथवा गतिविधि में संलग्न रहता है तो लेखा विवरण आयोग द्वारा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के अन्य कारोबार के निपटारे हेतु बनाए गए विनियमों के अनुपालन - स्वरूप होने चाहिए तथा उसमें राजस्व, लागत, आस्तियाँ, दायित्व, आरक्षित धन या प्रावधान को, जो या तो:-

(क) किसी अनुज्ञप्त कारोबार से भिन्न, जिसका किसी अन्य कारोबार पर प्रभार, हो, या प्रभारित किया गया हो, उस प्रभार के आधार के विवरण सहित, या

(ख) अनुज्ञप्त कारोबार और व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के अन्य कारोबार के सम्बन्ध में प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित हो; प्रभाजन या आबंटन के आधार के विवरण सहित, अलग से दर्शाया जाएगा ;

(3) "वार्षिक लेखे" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्धों और/अथवा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा निदेशित अन्य रीति से व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए लेखे अभिप्रेत हैं;

(4) "कार्य क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो व्यापारिक अनुज्ञप्ति में दिया गया कार्य क्षेत्र है, और जिसमें व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को व्यापार करने का अधिकार है ;

(5) "संपरीक्षक" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 से 234-क या धारा 619, जैसे भी समुचित हो, के अनुसार व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी का पदधारित संपरीक्षक अभिप्रेत है ;

(6) "प्राधिकृत" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति, कारोबार या गतिविधि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुकों के अधीन प्रदत्त समझी गई या अधिनियम की धारा 13 और आयोग के विनियमों के अधीन दी गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत, अभिप्रेत है ;

(7) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, अभिप्रेत है ;

(8) "समझा गया अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुकों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(9) "वितरण" से वितरण प्रणाली के साधनों द्वारा विद्युत का चक्रण व पारेषण अभिप्रेत है ;

(10) "वितरण कोड" से संयोजनों (कनैक्शनों) की बावत सभी महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं तथा वितरण प्रणाली के प्रचालन एवं प्रयोग हेतु आयोग के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कोड अभिप्रेत है;

(11) "अपरिहार्य घटना" से अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे की घटनाएँ अभिप्रेत हैं जिनमें भुकम्प, तुफान, बाढ़, आँधी, प्रतिकूल मौसम प्रभाव, युद्ध, आतंकवादी हमले, सिविल उपद्रव या अन्य ऐसी घटनाएँ जिन में विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित सुसंगत विधियों या विनियमों का उल्लंघन अंतर्निहित होता हो, किन्तु इन तक सीमित नहीं है;

(12) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इस में अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड भी सम्मिलित है;

(13) "अन्तरिम ग्रिड कोड" से उस समय तक जब तक अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(14) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति, जिसके अधीन अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है, अभिप्रेत है ;

(15) "अनुज्ञप्त कारोबार" से व्यापारिक अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत विद्युत में व्यापार अभिप्रेत है ;

(16) "अन्य कारोबार" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति कारोबार से, अनुज्ञप्तिधारी का अन्य कारोबार ;

(17) "विशेष शर्तों" का अभिप्राय साधारण शर्तों के अतिरिक्त या उनसे भिन्न शर्तों से है, जो आयोग द्वारा किसी व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के लिए विशेष रूप में निर्धारित की जाएं ;

(18) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(19) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(20) "व्यापारिक कारोबार" से व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी का कारोबार अभिप्रेत है; जिसमें वह अपनी ओर से या किसी अन्य की ओर से, अपने अधिपत्य वाली प्रणाली और/या उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रचालित प्रणाली के माध्यम से विद्युत प्रेषित करने के लिये प्राधिकृत है;

(21) "व्यापारिक अनुज्ञप्ति" से विद्युत व्यापार के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है; और उसमें इस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समझी गई अनुज्ञप्ति भी है ;

(22) "व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी" से विद्युत व्यापारी अभिप्रेत है और इसमें समानुज्ञप्तिधारी जो अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा पंचम परन्तुकों के अधीन विद्युत में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत है, भी आता है ;

(23) "अंतरण" में विक्रय, विनिमय, दान, पट्टा, अनुज्ञप्ति, ऋण, प्रतिभूतिभरण, बन्धक, अनुज्ञप्ति भार, गिरवी या कोई अन्य ऋणभार या भौतिक अधिपत्य के साथ किसी ऋणभार की सहायता करना या उसे त्यागना या अन्य कोई व्ययन या संव्यवहार सम्मिलित है ;

(24) अन्य सभी शब्दों, पदों व अभिव्यक्तियों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, और इन में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में नियत किया गया है ।

3. अवधि.— व्यापारिक अनुज्ञप्ति आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूरी के आदेश में उल्लिखित तारीख से प्रवृत्त होगी तथा अनुज्ञप्ति में मंजूर निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए आदेश में उल्लिखित कालावधि तक लागू रहेगी ।

4. विधि, नियमों व विनियमों का पालन.— (1) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम, नियमों, आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये विनियमों, आदेशों व निदेशों और अन्य सभी प्रवृत्त विधियों के प्रावधानों का पालन करेगा ।

(2) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, केवल जहां व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को व्यापारिक

अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति मन्जूर होने के समय अथवा आयोग द्वारा विशेष तौर से इनमें बदलाव हेतु दी गई मन्जूरी से इन शर्तों के प्रावधानों के पालन में छूट मिली हो के अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा ।

(3) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, ग्रिड कोड, वितरण कोड, प्रदाय विनियमों, प्रदाय शर्तों तथा अन्य कोड और मानकों का तथा राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जारी आदेशों व निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करेगा और उनके अनुरूप अपनी गतिविधियाँ संचालित करेगा ।

5. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कृत्य.— (1) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी राज्य में विद्युत में व्यापार कर सकेगा :

परन्तु यह कि जहाँ दूसरों के साथ उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय या प्रदाय है, वहाँ उक्त व्यापार अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित चालू स्तर की प्रति-सहायकी को पूरा करने के लिए अधिभार के भुगतान करने पर ही किया जाएगा ।

(2) राज्य में किसी व्यक्ति को विद्युत का पारेषण नहीं करेगा ।

(3) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की पूर्व मन्जूरी के बिना—

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के क्रय या उसका प्रबन्ध ग्रहण करने या उसे अन्यथा अर्जित करने के लिए कोई संव्यवहार नहीं करेगा;

(ख) किसी उत्पादन कम्पनी अथवा उत्पादन केन्द्र में फायदाप्रद हित अर्जित नहीं करेगा ; या

(ग) विद्युत वितरण का कारोबार नहीं करेगा ।

(4) ऐसे प्रकरण को छोड़कर जबकि अनुज्ञप्त कारोबार के प्रयोजन के लिए ऋण दिया या जारी किया गया हो व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को ऋण देने या किसी

बाध्यता के लिए कोई प्रतिभूति जारी करने से पूर्व आयोग की मन्जूरी प्राप्त करेगा, कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसरण में ऋण और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में व्यापार अग्रिम प्राप्ति हेतु को ऐसे मन्जूरी प्राप्त करने की अपेक्षा से अपवर्णित किया जाता है ।

(5) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के पूर्वनुमोदन के बिना, अपनी अनुज्ञप्ति को किसी भी समय किसी प्रकार से आंतरित अथवा अभ्यर्पित नहीं करेगा ।

6. लेखे.—(1) अधिकतम पूंजी संघटन अवधारित करने के लिए व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अपने कुल वित्तीय नियोजन, बजट तथा संरचना [जिस में वे प्रमुख वित्तीय प्राचल (पैरामीटर) जो व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अपने निष्पादन का अनुश्रवण (मनीटर) करने के लिए अपनाएगा, भी हैं] का अध्ययन करवाएगा ।

(2) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न हो, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त कारोबार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष इन विनियमों में अन्तर्विष्ट सामान्य शर्तों व मामलों के प्रयोजन हेतु प्रथम अप्रैल से आरम्भ हो कर आगामी 31 मार्च तक चलेगा ।

(3) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त कारोबार और किसी अन्य कारोबार के सम्बन्ध में,—

(क) ऐसे लेखा अभिलेख रखेगा जो प्रत्येक ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में अपेक्षित होगा जिससे कि अनुज्ञप्त कारोबार को युक्तियुक्त रूप में लगाने योग्य राजस्व, लागत, अस्तित्वों, दायित्वों, आरक्षितियों और निवेश, को व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तकों में उन अन्य कारोबार से, जिनमें व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी लगा हुआ है, पृथक्कृत: अभिज्ञेय हैं;

(ख) ऐसे लेखा अभिलेखों से प्रचलित आधार पर निम्न लेखा विवरण तैयार कर आयोग को भेजेगा—

(1) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मास के सम्बन्ध में ऐसे आधारीय दस्तावेजों और जानकारी सहित, यथा आयोग समय-समय पर निर्दिष्ट करे, अर्ध-वार्षिक लाभ-हानि लेखा, नकद प्रवाह कथन और तुलन-पत्र; (उक्त कथन और दस्तावेज उस रीति से, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित किए जाएंगे);

- (2) तैयार लेखा विवरण के सम्बन्ध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये यह अधिकारित करते हुए किसी संपरीक्षक की रिपोर्ट में यह बताया गया हो कि क्या उनकी राय में इन विवरणों को उचित रूप में तैयार किया गया है और वे राजस्व, लागत, अस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों और निवेशों का, अथवा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में माना जा सकने वाले का, जिनसे विवरण सम्बन्धित है, सत्य और आज्ञा दृष्टिकोण देते हैं;
- (3) प्रत्येक आधे वर्ष के लिए लाभ हानि लेखे की एक प्रति देगा, जो उस अवधि में जिस से वह सम्बन्धित है के तीन माह के पश्चात् के न हो, और लेखा विवरण तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट देगा जो उस वित्तीय वर्ष, जिस से वह सम्बन्धित है, की समाप्ति के पश्चात् की न हो ;
- (4) व्यापारिक अनुज्ञापिधारी आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना, पूर्व वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लागू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लेखा विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में भार या अनुपात या राजस्व का आवंटन या व्ययों के आधार को सामान्यतः परिवर्तित नहीं करेगा । भार या राजस्व के अनुपात या व्यय में, यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो, तो वह कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के लेखा मानकों या विनियमों और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा ;
- (5) जहां किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लेखा विवरण में व्यापारिक अनुज्ञापिधारी ने अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत भार या अनुपात या आवंटन के आधार को परिवर्तित कर दिया है, तो व्यापारिक अनुज्ञापिधारी, यदि आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर उस आधार पर, जो अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लागू होता था, ऐसे लेखा विवरण तैयार करेगा ;
- (6) उप-विनियम (3) के अधीन वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित या निर्दिष्ट न कर दिया जाए,—

(क) यहां दिए गए तरीके से व्यापारिक अनुज्ञापिधारी के वार्षिक लेखे तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे ;

- (ख) अभीकृत की गई लेखा नीतियों को अधिकृत करेंगे,
- (ग) सामान्यतः स्वीकार किए गए भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप तैयार किए जाएंगे,
- (घ) आयोग द्वारा समय-समय पर नियत किए गए स्वरूप के अनुसार तैयार किये जाएंगे।

(7) अनुज्ञापत कारोबार या अन्य कारोबार में युक्तियुक्त रूप में लगने योग्य व्ययों के दावेत्यों हेतु संदर्भित ऐसी पूंजीगत आंशितियों, जो कि सिद्धान्तिक रूप से ऐसे कारोबार और उस पर ब्याज से सम्बन्धित हैं, एवं कराधान को छोड़कर, मानी जाएंगी।

(8) व्यापारिक अनुज्ञापिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (3) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लेखा विवरण और प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में संपरीक्षक रिपोर्ट, आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से, प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी प्रति द्विप्रतिलिपिकरण के युक्तियुक्त मूल्य से अनाधिक की कीमत पर किसी भी व्यक्ति के अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध करवाई जाए।

7. आयोग को जानकारी देने के उपबन्ध:- (1) व्यापारिक अनुज्ञापिधारी आयोग को अविलम्ब ऐसी जानकारी, अभिलेख अथवा व्यापारिक अनुज्ञापिधारी के या किसी अन्य कारोबार से सम्बन्धित विवरण जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर उसके स्वयं के प्रयोजन के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य पारेषण उपयोगिता और राज्य भार पेशण केन्द्र, केन्द्रीय आयोग और या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित समझा जाए, प्रस्तुत करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञापिधारी अधिनियम की धारा 128 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट सूचना रखेगा।

(3) व्यापारिक अनुज्ञापिधारी आयोग को किसी भी घटना जो उसे गन्जूर अनुज्ञापि के अधीन बाधगताएँ, जिसमें दूसरों के कार्य या लोप से होने वाले कृत्य भी सम्मिलित हैं, निभाने से निर्बन्धित करे, तथा वितरण अनुज्ञापिधारी द्वारा ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में सम्यक् रूप में सूचित करेगा। व्यापारिक अनुज्ञापिधारी यथासम्भव शीघ्र आयोग को उसकी व्यापारिक गतिविधियों को अधिक मात्रा में प्रभावित करने वाली किसी घटित अन्य घटना को और ऐसी घटना होने की तारीख से दो मास के भीतर, आयोग को

अधिरूचित करेगा :-

- (क) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी की जानकारी में घटना तथा उसके कारणों के सम्बन्ध में तथ्यों का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (ख) घटना के पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट देने के लिए दो माह से अधिक समय क्यों अपेक्षित है, का व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी युक्तिगुत्त विवरण देगा;
- (ग) प्रमुख घटना से सम्बन्धित सभी पक्षकारों और अन्य ऐसे व्यक्तियों, जिन के लिए आयोग द्वारा निदेशित किया जाए, को रिपोर्ट की प्रतियाँ देगा ।

(4) जिसे आयोग लोक हित में व्यापारिक गतिविधियों तथा व्यापारिक कारोबार के सम्बन्ध में उचित समझता हो, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे विन्दुओं का अध्ययन करेगा । अनुकल्पतः आयोग, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर, अपने आप भी अध्ययन कर या परामर्शियों से करवा सकता है, उक्त खर्चा समेकित राजस्व गणना (ARR) में अनुज्ञात किया जायेगा ।

(5) आयोग, किसी भी समय इस विनियम के उपबन्धों का, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, पालन करने की व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकता है और व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा ।

(6) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारिक अनुज्ञप्ति के लागू होने के तीन माह के भीतर आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि हेतु कारोबार योजना प्रस्तुत करेगा और उसका वार्षिक रूप से अद्यतन करेगा । कारोबार योजना में वर्ष-वार व्यापारवर्त, संभावित लाभ-हानि लेखे, संभावित तुलन-पत्र, संभावित रोकड़ उपलब्धता विवरण और संभावित महत्वपूर्ण वित्तीय प्राचल (पैरामीटर्स) सम्मिलित होंगे ।

8. पूर्जी पर्याप्तता, ऋण अर्हता सन्नियमों का अनुपालन.—(1) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, विनियमों, मार्गदर्शक सिद्धान्तों, निदेशों तथा आदेशों, जो आयोग तकनीकी तथा वित्तीय प्रचाल (पैरामीटर) के सम्बन्ध में, समय-समय पर जारी करे, तथा उन सन्नियमों का जो व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आम तौर पर अपनाए जाते हैं का सम्यक् रूप से पालन करेगा । इनमें अधिनियम की धारा 52 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट विद्युत व्यापारी की तकनीकी अपेक्षाएँ, पूर्जी पर्याप्तता तथा ऋण अर्हता भी सम्मिलित हैं ।

(2) उप विनियम (1) के अधीन तकनीकी तथा वित्तीय प्रचालन का पालन न करना,

व्यापारिक अनुज्ञापिधारी की बायताओं का प्रमुख उल्लंघन होगा ।

9. अनुज्ञापि शुल्क का भुगतान.— (1) ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी शीति में, जैसे कि आयोग निर्दिष्ट करे, व्यापारिक अनुज्ञापिधारी आयोग को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 या विशेष शर्तों में उल्लिखित प्रारम्भिक और सामायिक अनुज्ञापि शुल्क का भुगतान करेगा ।

(2) जहाँ व्यापारिक अनुज्ञापिधारी शोध्य तिथि तक उप-विनियम (1) के अधीन किसी भी देय शुल्क का भुगतान आयोग को करने में अराफल रहता है, वहाँ —

(क) अन्य दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यापारिक अनुज्ञापिधारी शेष देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज बकाया रकम पर देने का दायी होगा । ब्याज उस दिन के पश्चात् की अवधि पर देय होगा जिसको कि रकम शोध्य होती है और उस दिन को समाप्त होगा जिस तारीख को आयोग को भुगतान किया जाता है ; तथा

(ख) व्यापारिक अनुज्ञापिधारी द्वारा लगातार बकाया होने की स्थिति में आयोग व्यापारिक अनुज्ञापि को प्रतिसंहरित कर सकता है ।

(3) व्यापारिक अनुज्ञापिधारी टैरिफ के लिए संकलित राजस्व के अवधारण में व्यय के रूप में इस विनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए गए किसी भी शुल्क को हिसाब में लेने का हकदार होगा ; परन्तु इस में देशी से किए गए भुगतान पर संदत्त ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

10. प्रतिसंहरण की शर्तें.—(1) अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों और उसके अधीन बने विनियमों के अधीन, आयोग किसी भी समय, व्यापारिक अनुज्ञापिधारी के विरुद्ध अनुज्ञापि के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा और यदि ऐसी कार्यवाहियाँ में प्रतिसंहरण के आधारों और लोकहित से उसका समाधान हो जाता है, तो वह निम्नलिखित दशा में व्यापारिक अनुज्ञापि का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ व्यापारिक अनुज्ञापिधारी आयोग की राय में अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में अपेक्षित कोई भी बात को करने में जानबूझकर और विलंबित व्यतिक्रम करता है ;

- (ख) जहाँ व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन से अनुज्ञप्ति अभेद्यक्त : प्रतिसंहत हो जाए;
- (ग) जहाँ व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति में नियत अवधि के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि जिसे आयोग ने प्रदान किया हो, के भीतर :-

- (1) आयोग को यह दर्शाने में असफल रहता है कि अनुज्ञप्ति में उसके ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ; या
- (2) अनुज्ञप्ति में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप करने या फीस या अन्य प्रभार का संदाय करने में असफल रहता है;

- (घ) जहाँ आयोग की राय में व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूर्णतः और दक्षता से निभाने में असमर्थ रहता है ; और
- (ङ) जहाँ व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी आयोग के सभी विनियमों, कोडों, और मानकों और आदेशों व निर्देशों के पालन में असफल रहता है या अन्यथा ऐसा कृत्य करता है, जिससे अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य आधारों पर व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरणीय हो जाए ।

(2) जहाँ उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो आयोग आवेदन प्राप्त होने पर या व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुज्ञप्ति को पूर्ण रूप से या उसके व्यापार क्षेत्र के किसी भाग के लिए ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझता हो, प्रतिसंहत कर सकेगा ।

(3) व्यापारिक अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने से पूर्व, आयोग, यदि उसकी राय में आवश्यक हो, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करेगा तथा उक्त सभी प्रबन्ध व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के खर्च तथा जोखिम पर होगा ।

11. अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.— (1) आयोग, यदि लोकहित में आवश्यक समझता हो, अधिनियम की धारा 18 के अधीन अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों में परिवर्तन और संशोधन निम्न शर्तों पर कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) जहाँ व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के

अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए आवेदन किया हो, वहाँ व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदन की सूचना को आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से और विशिष्टियों सहित प्रकाशित करेगा;

- (ख) किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प के या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के अधिभोग में/के किसी भवन या स्थान के सभी या किसी भाग को समाविष्ट करने वाले कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या उपांतरण का प्रस्ताव करने वाले आवेदन की दशा में, कोई भी परिवर्तन या उपांतरण केवल केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा ;
- (ग) जहाँ किसी अनुज्ञप्ति में किसी व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से अन्यथा कोई परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया हो, आयोग ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन को ऐसी विशिष्टियों सहित और ऐसी रीति से प्रकाशित करवाएगा, जैसे आयोग उचित समझे ;
- (घ) आयोग कोई भी परिवर्तन या संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार न कर लिया हो ।

12. विवाद समाधान.— (1) आयोग को अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 158 और आयोग के विनियमों के अनुसरण में व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनी के बीच विवाद को न्यायनिर्णित करने या हल करने के लिए मध्यस्थता करने अथवा किसी व्यक्ति को माध्यस्थता के रूप में मनोनीत करने का अधिकार होगा ।

(2) आयोग, यथास्थिति, स्वयं उप-विनियम (1) के अधीन विवादों की माध्यस्थता कार्यवाई को प्रारम्भ और संचालित कर सकता है या विवादों को आयोग के कारोबार संचालन विनियमों के अनुसार अन्य की मध्यस्थता के लिए निवेदित कर सकता है ।

13. व्यापार मुनाफा (लाभ) तथा सम्भावित राजस्व गणना .— (1) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम, आयोग के विनियमों, टैरिफ के निबंधनों व शर्तों व आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य मार्गदर्शन, आदेशों और निर्देशों के उपबन्धों के अनुसार प्रभाओं, जिसे उसे व्यापार मुनाफा के रूप में प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, से सम्भावित

राजस्व की गणना करेगा।

(2) व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी सम्भावित राजस्व गणना अधिनियम की धारा 61 के अधीन विनियमों में दिए गए उपबन्धों के अनुसार परतृत करेगा।

(3) जब तक विशेष शर्तों या आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्देश द्वारा अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष, 30 नवम्बर तक आयोग को अधिनियम और उसके अधीन आयोग द्वारा, समय-समय पर जारी, विनियमों, दिशा-निर्देशों और आदेशों के उपबन्धों के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष की, आयोग द्वारा अनुज्ञात व्यापार मुनाफा के आधार पर, सम्भावित संकलित राजस्व और सेवा लागत (जिसमें लागत वित्तपोषण और अकिविटी पर इसकी सम्भावित आय सम्मिलित है) का विस्तृत विवरण देगा।

14. विविध.— (1) इन विनियमों की और उनकी शर्तों के बारे में व्याख्या से सम्बन्धित उठने वाले सभी विवादक आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे और ऐसे विवादकों पर आयोग का विनिश्चय केवल अधिनियम की धारा 111 के अधीन करने के अधिकार के अध्याधीन अन्तिम होगा।

(2) आयोग व्यापारिक अनुज्ञप्ति मन्जूर करते समय, या तो अनुज्ञप्ति मन्जूर करने वाले आदेश में या किसी विनिर्दिष्ट व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होने वाली विशेष शर्तों द्वारा इन विनियमों के किसी भी लागू उपबन्ध का अधित्यजन या उपात्तरण कर सकता है।

15. समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू उपबन्ध.— अधिनियम लागू होने पर व्यापारिक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सभी आवेदकों, और अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पाँचवे परन्तुकों के अधीन सभी समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों, पर एतद्वारा दी गई सामान्य शर्तें लागू होंगी।

16. कठिनाईयें दूर करना.— (1) आयोग, अधिनियम के अध्याधीन रहते हुए, समय-समय पर, इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में, जिसके लिए आयोग को इन विनियमों द्वारा और उनसे सम्बन्धित, प्रासंगिक या आनुषंगिक मामलों में निर्देश देने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश अथवा पद्धति निर्देश दे सकता है।

(2) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी समुचित कार्यवाई

करने या करने को मानने के लिए कह सकता है, जो आयोग की राय में कतिनाइयों को पूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन लगे।

(3) इस विनियम के अधीन कोई भी आदेश इन विनियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगा और उसकी जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

17. निरसन और अपवाद.— (1) इन विनियमों में जैसा उपबन्धित है, उसकी शिवाय, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 या अन्य किसी विधि के अधीन व्यापारिक अनुज्ञापिका के लिए जारी सामान्य या विशेष शर्तों को, जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व लागू हों, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, व्यापारिक अनुज्ञापिका की निरस्त सामान्य या विशेष शर्तों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या अभिप्रेत कार्रवाई, जब तक इन विनियमों के उपबन्धों से अनसंगत न हो, के इन विनियमों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया गया समझा जाएगा।

(3) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व जारी व्यापारिक अनुज्ञापिका की विशेष शर्तें और निर्देश (जिसमें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन सुनवाई के दौरान दैरिफ आदेश, 2001-02 के अध्याय 7 में उल्लिखित निर्देश सम्मिलित हैं), जो इन विनियमों के उपबन्धों से अनसंगत नहीं हैं, उस अवधि तक लागू रहेंगे जब तक के लिए ऐसी सामान्य या विशेष शर्तें या निर्देश जारी किए गए थे।

शिमला, 30 सितम्बर, 2005

संख्या एच0 पी0 इ0 आर0 सी/413.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003, (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) सहित पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस द्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या एच.पी.इ.आर.सी/381 दिनांक 10-6-2004 द्वारा बनाये तथा आयोग की अधिसूचना संख्या एच.पी.इ.आर.सी/381 दिनांक 2-2-2005 द्वारा संशोधित किए गए हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जनरल

कम्प्लैशनज आफ् ट्रांसमिशन) रेगुलेशनज, 2004, किन्हीं कारणां से जिनका हिन्दी भात प्रकाशित नहीं हो पाया है, का निम्न हिन्दी भात प्रकाशित करता है:-

विनियम

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण अनुज्ञप्ति को सामान्य शर्तें) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम 10 जून, 2004 से लागू होंगे।

2. पारभाषाएँ- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "आधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) "लेखा विवरण" से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में दिए गए विवरण के अनुसार अनुज्ञप्त कारोबार का लेखा विवरण, अभिप्रेत है जिसमें लाभ-हानि लेखा, तुलन-पत्र और संसाधनों का तथा निधियों की प्रायोज्यता का टिप्पणियों सहित विवरण तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निदेशित अन्य ऐसे विवरण व व्यौरे समाविष्ट होंगे। यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार के अतिरिक्त किसी अन्य कारोबार अथवा गतिविधि में संलग्न रहता है तो लेखा विवरण आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अन्य कारोबार के निपटारे हेतु बनाए गए विनियमों के अनुपालन - स्वरूप होने चाहिए तथा उसमें राजस्व, लागत, आस्तियाँ, दायित्व, आरक्षित धन या प्रावधान को, जो या तो -

(क) किसी अनुज्ञप्त कारोबार से भिन्न, जिसका किसी अन्य कारोबार पर प्रभार हो, या प्रभारित किया गया हो, उस प्रभार के आधार के विवरण सहित, या

(ख) अनुज्ञप्त कारोबार और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के अन्य कारोबार के सम्बन्ध में प्रभाजन या आबटन द्वारा अवधारित हो; प्रभाजन या आबटन के आधार के विवरण सहित, अलग से दर्शाया जाएगा ;

(3) "वार्षिक लेखे" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्धों और/अथवा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा निदेशित अन्य रीति से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए लेखे अभिप्रेत हैं;

(4), "कार्य क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो पारेषण अनुज्ञप्ति में दिया गया कार्य क्षेत्र है, और जिसमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को पारेषण लाईनें स्थापित, परिचालित और सम्मोषित करने का अधिकार है,

(5) "संपरीक्षक" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 से 234 का या धारा 619, जैसे भी समुचित हो, के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का पदधारित संपरीक्षक अभिप्रेत है,

(6) "प्राधिकृत" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति, कारोबार या गतिविधि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुकों के अधीन प्रदत्त समझी गई या अधिनियम की धारा 13 और आयोग के विनियमों के अधीन दी गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत, अभिप्रेत है;

(7) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, अभिप्रेत है,

(8) "वितरण" से वितरण प्रणाली के साधनों द्वारा विद्युत का चक्रण व पारेषण अभिप्रेत है ;

(9) "वितरण कारोबार" से प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी प्रदाय क्षेत्र के उपभावताओं को विद्युत प्रदाय हेतु वितरण प्रणाली को परिचालित तथा सम्मोषित करने के लिए वितरण कारोबार अभिप्रेत है;

(10) "वितरण कोड" से संयोजनों (कनैक्शनों) की बावत सभी महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं तथा वितरण प्रणाली के प्रचालन एवं प्रयोग हेतु आयोग के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कोड अभिप्रेत है;

(11) "विद्यमान पारेषण प्रणाली के प्रचालन मानकों" से राज्य में अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने की तारीख को यथा लागू पारेषण प्रणाली के प्रचालन हेतु मानक, तथा नये कारोबार की दशा में वे मानक जो अन्य या पूर्वोक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू हों, अभिप्रेत हैं,

(12) "विद्यमान पारेषण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानकों" से राज्य में अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने की तारीख को लागू पारेषण प्रणाली योजना व पारेषण प्रणाली सुरक्षा मानक, तथा नये कारोबार की दशा में वे मानक जो अन्य या पूर्वोक्त पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू हों,

अभिप्रेत हैं;

(13) "अपरिहार्य घटना" से अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे की घटनाएँ अभिप्रेत हैं जिनमें भुकम्प, तुफान, बाढ़, आँधी, प्रतिकूल मौसम प्रभाव, युद्ध, आतंकवादी हमले, सिविल उपद्रव या अन्य ऐसी घटनाएँ जिन में विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित सुसंगत विधियों या विनियमों का उल्लंघन अंतर्निहित होता हो, किन्तु इन तक सीमित नहीं है;

(14) "अन्तःसंयोजन जनित्र सुविधाएँ" से जनित्र सैटों द्वारा पारेषण या वितरण प्रणाली तक पहुँच के लिए प्रयुक्त की गई विद्युत लाईनों, ट्रांसफार्मरों, बस-बारों, स्विचगियर, संयंत्र या साधित्र अभिप्रेत हैं;

(15) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इस में अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड भी सम्मिलित है;

(16) "नियंत्री (होल्डिंग) कम्पनी" का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 में उसका है ;

(17) "अन्तरिम ग्रिड कोड" से उस समय तक जब तक अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा उस तारीख को जिसको पारेषण अनुज्ञप्ति के निबन्धन एवं शर्तें जारी की गई हों, पारेषण के प्रचालन में अपनाई जाने वाली विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(18) "मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएँ" से जहाँ किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उस के अनुरोध पर तथा टैरिफ या प्रभार के संदाय पर विद्युत पारेषण के लिए विद्युत लाइनें प्रयोग में लाई जाती हैं, वहाँ वे विद्युत लाइनें जिनका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी स्वामी हो, या जिन्हें प्रचालित करता हो, अभिप्रेत हैं ;

(19) "अनुज्ञप्ति" से अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति जिसके अधीन अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है, अभिप्रेत है ;

(20) "अनुज्ञप्त कारोबार" से पारेषण अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत विद्युत पारेषण कारोबार

अभिप्रेत है ;

(21) "प्रमुख घटना" से अभिप्रेत है विद्युत के पारेषण से जुड़ी ऐसी घटना जिसका परिणाम सेवा के विशिष्ट व्यवधान, उपकरणों को अधिक नुकसान या मानव जीवन को हानि या उल्लेखनीय चोट या आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के रूप में हों, और इस में ऐसी अन्य घटना, जिसे आयोग स्पष्टतः प्रमुख घटना घोषित करे, भी सम्मिलित होंगी ;

(22) "प्रचालन नियंत्रण" से अभिप्रेत है प्रचालन विनिश्चय को प्राधिकृत करने का अधिपत्य रखना, जैसे कि इकाईयों, सेवा लाईनों व उपस्करों का प्रवर्तन और उपयोगिकरण;

(23) "अन्य कारोबार" से अभिप्राय अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त कारोबार से भिन्न अन्य कारोबार से है;

(24) "निष्पादन मानक" से आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अनुसरण में अवधारित मानक अभिप्रेत हैं;

(25) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(26) "समनुषंगी" का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 में उसका है;

(27) "अंतरण" में विक्रय, विनिमय, दान, पट्टा, अनुज्ञप्ति, ऋण, प्रतिभुतिभरण, बन्धक, अनुज्ञप्ति भार, गिरवी या कोई अन्य ऋणभार या भौतिक अधिपत्य के साथ किसी ऋणभार की सहायता करना या उसे त्यागना या अन्य कोई व्ययन या संव्यवहार सम्मिलित है;

(28) "पारेषण कारोबार" से अभिप्रेत है विद्युत पारेषण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व की किसी पद्धति और/या प्रचालित कोई ऐसा प्राधिकृत कारोबार चाहे स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो ;

(29) "पारेषण अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसी सत्ता (equity) अभिप्रेत है जिसे विद्युत पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है या अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुकों के अधीन प्रदत्त की गई समझी गई है, अभिप्रेत है ;

(30) "पारेषण प्रचालन मानक" से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली के

प्रचालन हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित मानक अभिप्रेत हैं;

(31) "पारेषण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक" से आयोग द्वारा यथानुमोदित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली की योजना और सुरक्षा की पर्याप्ता संबंधित मानक अभिप्रेत हैं ;

(32) "पारेषण प्रणाली" से अभिप्रेत है 33 किलोवोल्ट या उस से अधिक की वोल्टेज डिजाईन की विद्युत लाईन जो कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के स्वामित्व या नियंत्रण में हो एवं दो स्वीचयार्ड के बीच विद्युत के वहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई या जनरेटिंग सेट के स्वीचयार्ड से किसी उपकेन्द्र या उपकेन्द्रों के बीच या किसी बाह्य अंतः संयोजन तक समस्त प्रणाली, उपस्कर और विद्युत के पारेषण के सम्बन्ध में उपयोग में लाए गए संयंत्र, उपस्कर और मीटर सम्मिलित हैं, किन्तु किसी वितरण प्रणाली का कोई भाग सम्मिलित नहीं है ;

(33) "प्रणाली का उपयोग" से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के साथ किये गए करार के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत के वहन के लिए पारेषण प्रणाली का उपयोग, अभिप्रेत है;

(34) "उपयोक्ता" से अभिप्राय पारेषण प्रणाली का उपयोग करने वाले से है;

(35) अन्य सभी शब्दों, पदों व अभिव्यक्तियों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, और इन में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में नियत किया गया है ।

3. अवधि.—पारेषण अनुज्ञप्ति आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूरी के आदेश में उल्लिखित तारीख से प्रवृत्त होगी तथा अनुज्ञप्ति में मंजूर निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए आदेश में उल्लिखित कालावधि तक लागू रहेगी ।

4. विधि, नियमों व विनियमों का पालन.—(1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम, नियमों, आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये विनियमों, आदेशों व निदेशों और अन्य सभी प्रवृत्त विधियों के प्रावधानों का पालन करेगा ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, केवल जहां पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति मन्जूर होने के समय अथवा आयोग द्वारा विशेष तौर से इनमें बदलाव हेतु दी गई मन्जूरी से इन शर्तों के प्रावधानों के पालन में छूट मिली हो के अतिरिक्त, इन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्य

करेगा।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जारी आदेशों व निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करेगा।

5. पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की गतिविधियाँ.— (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 40 के अधीन यथा उपबन्धित पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(2) पारेषण लाईनों में पारेषण क्षमता उपलब्ध होने पर और, जब उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय के लिए पारेषण प्रणाली का उपयोग किया जाता है, अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 40 में यथा उपबन्धित करंट लेवल प्रतिसहायकी को पूरा करने के लिए विद्युत प्रदाय के लिए प्रभारों के भुगतान करने पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कम्पनियों जिन में आबद्ध उत्पादन संयंत्र भी हैं, के प्रयोग हेतु पारेषण प्रणाली में अविभेदकारी खुली पहुँच उपलब्ध करेगा।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की पूर्व मन्जूरी के बिना—

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के क्रय या उसका प्रबन्ध ग्रहण करने या उसे अन्यथा अर्जित करने के लिए कोई संयवहार नहीं करेगा;

(ख) किसी उत्पादन कम्पनी अथवा उत्पादन केन्द्र में फायदाप्रद हित अर्जित नहीं करेगा ; या

(ग) अनुज्ञप्ति के अधीन प्राधिकृत न होने वाले किसी व्यक्ति को राज्य में विद्युत पारेषित नहीं करेगा।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत में व्यापार नहीं करेगा और वह प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी विद्युत व्यापारी या वितरण अनुज्ञप्तिधारी से सम्बद्ध नहीं होगा।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी पारेषण प्रणाली में उपलब्ध अधिशेष क्षमता तक मध्यवर्ती पारेषण सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा तथा यदि अधिशेष क्षमता की उपलब्धता के बारे कोई विवाद उत्पन्न है, तो उसका निर्णय आयोग करेगा। मध्यवर्ती सुविधाओं

के प्रयोग हेतु देय प्रभार, शर्तें और निबन्धन, आयोग द्वारा इस निमित्त जारी आदेश के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आपसी सहमति से तय किए जाएंगे। किसी असहमति की स्थिति में उसका विनिश्चय आयोग करेगा।

(6) यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य कारोबार में अनुरत हो, तो वह निम्न शर्तों के अध्यक्षीन ऐसा कर सकता है कि —

- (क) अनुज्ञप्ति पारेषण कारोबार एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की कार्य प्रणाली में पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए तथा किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ;
- (ख) ऐसे कारोबार से प्राप्त राजस्व के भाग का उपयोग आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट पारेषण एवं चक्रण प्रभारों को न्यून करने में किया जा सके ;
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी अन्य कारोबार की गतिविधियों के सम्बन्ध में पृथक लेखा अभिलेख तैयार करेगा और रखेगा जो कि ऐसी गतिविधियों के सम्बन्ध में यदि ऐसी गतिविधियाँ पृथक कम्पनी द्वारा की जाती रखा जाना अपेक्षित हो ताकि राजस्व लागतें, अस्तियाँ, दायित्व, आरक्षित निधि एवं ऐसे उपबन्ध उन अनुज्ञप्त कारोबार एवं अन्य कारोबार गतिविधियों से पृथक रूप से पहचानने योग्य हों;
- (घ) अनुज्ञप्त कारोबार प्रतिष्ठान पारेषण कारोबार द्वारा पोषित नहीं होगा तथा किए गए कारोबार की सहायता हेतु पारेषण सम्पदाओं पर कोई भार उत्पन्न नहीं करेगा ;
- (ङ) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली या अन्य कोई उपयोगी वस्तुएँ जो पारेषण कारोबार के उपयोग में आ रही हों का अंतरण किसी अन्य कारोबार की गतिविधियों में आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं करेगा।

(7) ऐसे प्रकरण को छोड़कर जबकि अनुज्ञप्त कारोबार के प्रयोजन के लिए ऋण दिया या जारी किया गया हो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को ऋण देने या किसी बाध्यता के लिए कोई प्रतिभूति जारी करने से पूर्व आयोग की मन्जूरी प्राप्त करेगा। कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसरण में ऋण और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में व्यापार अग्रिम प्राप्ति हेतु ऐसी मन्जूरी प्राप्त करने की अपेक्षा से अपवर्णित किया जाता है।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्त कारोबार के सम्बन्ध में, माल तथा सेवाएँ

उपलब्ध करने के लिए निम्न शर्तों के अध्याधीन, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की किसी भी नियंत्री या समनुषंगी कम्पनी या ऐसी नियंत्री कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी को अनुबंधित कर सकता है,—

- (क) यह कि संव्यवहार अतिपरिचित आधार पर होगा और ऐसे मूल्य पर होगा जो कि परिस्थितियों के अनुरूप उचित और युक्तियुक्त हों;
- (ख) यह कि अनुज्ञप्त कारोबार के सम्बन्ध में माल तथा सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए संव्यवहार आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के संगत हों; और
- (ग) यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित व्यवस्था के प्रारम्भ होने से पूर्व, आयोग को 15 दिन का नोटिस देगा और नोटिस के साथ समस्त सुसंगत विवरण उपलब्ध करेगा ।

(9) नियंत्री या समनुषंगी कम्पनी या किसी नियंत्री कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी की ऐसी प्रयुक्ति के समस्त अन्य प्रकरणों में आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी । जहाँ ऐसी अनुमति आवश्यक हो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष पूर्ण तथ्यों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा । आवेदन प्रस्तुत करने की 30 दिवस की अवधि में आयोग आवेदन के समर्थन में अन्य जानकारी माँग सकता है । ऐसी अन्य जानकारी चाहने के 30 दिवस के अन्दर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जानकारी प्रस्तुत किये जाने पर या जहाँ अतिरिक्त जाँच अपेक्षित नहीं है, आयोग सामान्यतः आवेदन प्रस्तुत करने के बाद 60 दिवस की अवधि में आवेदित व्यवस्थाओं को ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर, ऐसे उपांतरण के साथ जो वह उचित समझे, स्वीकार/अस्वीकार कर सकेगा । आयोग द्वारा पारित ऐसे आदेश में निर्णय के कारण अधिलिखित किये जायेंगे ।

(10) बिना आयोग के पूर्व अनुमोदन के पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय अपनी अनुज्ञप्ति या इकाई या उसके किसी अंश को विक्रय, पट्टे, विनियम या अन्य प्रकार से किसी अन्य को अंतरित या सौंप नहीं सकेगा ।

6. लेखे.— (1) अधिकतम पूंजी संघटन अवधारित करने के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने कुल वित्तीय नियोजन, बजट तथा संरचना (जिस में वे प्रमुख वित्तीय प्राचल (पैरामीटर) जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपने निष्पादन का अनुश्रवण (मनीटर) करने के लिए अपनाएगा, भी हैं) का अध्ययन करवाएगा ।

(2) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त

कारोबार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष सामान्य शर्तों व मामलों के प्रयोजन हेतु इन विनियमों के लिए प्रथम अप्रैल से आरम्भ हो कर आगामी 31 मार्च तक चलेगा ।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त कारोबार और किसी अन्य कारोबार के सम्बन्ध में,—

(क) ऐसे लेखा अभिलेख रखेगा जो प्रत्येक ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में अपेक्षित होगा जिस से कि अनुज्ञप्त कारोबार को युक्तियुक्त रूप में लगाने योग्य राजस्व, लागत, अस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों और निवेश को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तकों में उन अन्य कारोबार से, जिनमें पारेषण अनुज्ञप्तिधारी लगा हुआ है, पृथक्कृत: अभिज्ञेय हैं;

(ख) ऐसे लेखा अभिलेखों से प्रचलित आधार पर निम्न लेखा विवरण तैयार कर आयोग को भेजेगा,—

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मास के सम्बन्ध में ऐसे आधारीय दस्तावेजों और जानकारी सहित, यथा आयोग समय-समय पर निर्दिष्ट करे, अर्ध-वार्षिक लाभ-हानि लेखा, नकद प्रवाह कथन और तुलन-पत्र (उक्त कथन और दस्तावेज आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति में प्रकाशित किए जाएँगे);

(ii) तैयार लेखा विवरण के सम्बन्ध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये यह अधिकथित करते हुए किसी संपरीक्षक की रिपोर्ट में यह बताया गया हो कि क्या उनकी राय में इन विवरणों को उचित रूप में तैयार किया गया है और ये राजस्व, लागत, अस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों और निवेशों का, अथवा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में माना जा सकने वाले का, जिनसे विवरण सम्बन्धित है, सत्य और ऋजु दृष्टिकोण देते हैं;

(iii) प्रत्येक आधे वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की एक प्रति देगा, जो उस अवधि में जिस से वह सम्बन्धित है के तीन माह के पश्चात् के न हो, और लेखा विवरण तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट देगा जो उस वित्तीय वर्ष, जिस से वह सम्बन्धित है, की समाप्ति के पश्चात् की न हो ।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना, पूर्व वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध

में लागू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लेखा विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में भार या अनुपात या राजस्व का आवंटन या व्ययों के आधार को सामान्यतः परिवर्तित नहीं करेगा। भार या राजस्व के अनुपात या व्यय में, यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो, तो वह कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के लेखा मानकों या विनियमों और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा।

(5) जहां किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लेखा विवरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत भार या अनुपात या आवंटन के आधार को परिवर्तित कर दिया है, तो वहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अंगीकृत आधार पर लेखा विवरण तैयार करने के अतिरिक्त यदि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाने पर उस आधार पर जो अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लागू होता है, लेखा विवरण तैयार करेगा और अयोग को सौंपेगा।

(6) उप-विनियम (3) के अधीन वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा रूप से आयोग द्वारा अनुमोदित या निदेशित न कर दिए जाए, -

- (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखे तैयार और प्रकाशित किए जाएँगे ;
- (ख) अंगीकृत की गई लेखा-नितियों को अधिकथित करेंगे ;
- (ग) सामान्यतः स्वीकार किए गए भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप के अनुसार तैयार किए जाएँगे;
- (घ) आयोग द्वारा समय-समय पर नियत किए गए स्वरूप के अनुसार तैयार किये जाएँगे।

(7) अनुज्ञप्त कारोबार या अन्य कारोबार में युक्तियुक्त रूप में लगने योग्य व्ययों के दायित्वों हेतु संदर्भित ऐसी पूंजीगत आस्तियाँ, जो कि सिद्धांतिक रूप से ऐसे कारोबार और उस पर ब्याज से सम्बन्धित हैं, एवं कराधान को छोड़कर, मानी जाएँगी।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (3) के अधीन तैयार किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लेखा विवरण और प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में संपरीक्षक रिपोर्ट, आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से, प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी प्रति द्विप्रतिलिपिकरण के युक्तियुक्त मूल्य से अनाधिक की कीमत पर किसी भी व्यक्ति के अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध

करवाई जाए।

१ आयोग की जानकारी देने की सम्बन्ध (१) पार्षद अनुज्ञापिकाधी आयोग को अतिरिक्त ऐसी जानकारी अतिरिक्त अथवा पार्षद अनुज्ञापिकाधी की या किसी अन्य कारीबार से सम्बन्धित विवरण जिसे आयोग द्वारा समय समय पर उसकी सेवा की प्रतीक्षा के लिए या भारत सरकार राज्य सरकार, केंद्रीय आयोग केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण राज्य पार्षद अनुज्ञापिकाधी और राज्य मंत्रालय केंद्र की प्रतीक्षा के लिए अतिरिक्त समझा जाए प्रस्तुत करेगा।

(२) पार्षद अनुज्ञापिकाधी अधिनियम की धारा १२४ की अधीन आयोग द्वारा गठानिर्देश शुभना रखेगा।

(३) पार्षद अनुज्ञापिकाधी गठानिर्देश शीघ्र आयोग को पार्षद अनुज्ञापिकाधी की किसी भाग को प्रभावित करने वाली किसी घटना प्रमुख घटना को और ऐसी घटना होने को तारीख से दो मास के भीतर आयोग को अधिसूचित करेगा।

(क) पार्षद अनुज्ञापिकाधी की जानकारी में घटना तथा उसकी कारणों की सम्बन्ध में तथ्यों का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

(ख) यदि खण्ड (क) की अधीन रिपोर्ट देने में ऐसी घटना की तारीख से दो मास से अधिक समय लगना सम्भाव्य हो तो पार्षद अनुज्ञापिकाधी घटना घटने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे सभी विवरणों जिसे पार्षद अनुज्ञापिकाधी उचित प्रकार से प्रस्तुत कर सकें, सहित एक प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उन कारणों जिनकी वजह से घटना की पूर्ण रिपोर्ट देने के लिए पार्षद अनुज्ञापिकाधी को दो मास से अधिक समय अतिरिक्त है, को अधिकांशित करेगा,

(ग) प्रमुख घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों और अन्य ऐसी व्यक्तियों, जिन के लिए आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए, को रिपोर्ट की प्रतियाँ देगा।

(४) आयोग स्वविवेकानुसार पार्षद अनुज्ञापिकाधी के द्वारा पर किसी स्वतन्त्र व्यक्ति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा कर सकेगा।

(५) पार्षद अनुज्ञापिकाधी, आयोग के विरुद्ध निर्देश पर, अनुज्ञाप पार्षद कारीबार के संघर्ष हेतु तथा पार्षद कारीबार से सम्बन्धित अन्य विषयों पर जिन्हें आयोग लोकहित में या

प्रमुख घटना की टीका है। आवश्यक समझी समझ पर अध्ययन करेगा। अनुकूलन आयोग प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं की श्रद्धा पर अपने आप भी अध्ययन कर सकता है या परामर्शियों द्वारा करवा सकता है। वह स्वयं उसकी समीक्षा समझ समझ (AIR) में अनुज्ञापन किया जाएगा।

(b) प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं आयोग द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट ऐसे बिन्दुओं का अध्ययन करेगा जिस से प्रारम्भ प्रणाली और प्रारम्भ कारीबार से जुड़े अन्य बिन्दुओं जिन्हें आयोग ऐसी घटना को घटित होने से टालने हेतु आवश्यक समझना ही में सुधार ही।

(f) विवरण अनुज्ञापिकाओं आयोग को किसी भी घटना जो उस मन्त्र अनुज्ञापन की अधीन बाधनाएँ, जिसमें प्रसंग की कार्य या लोग से होने वाले कृत्य भी सम्मिलित हैं, निगाने में बाधक ही तथा प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं द्वारा ऐसी घटना की प्रभाव को कम करने हेतु उदात्त माप कार्यों की बारे में सम्यक रूप में सूचित करेगा।

(g) आयोग किसी भी समय उप विनियम (३) से (b) की उपायों का जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, पालन करने की प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं से अपेक्षा कर सकता है और प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा। मने ही ऐसी घटनाएँ प्रमुख घटनाएँ भी हों, परन्तु उप विनियम (३) में विनिर्दिष्ट समय सीमा उस विशेष से प्रारम्भ होगी जिस विशेष को आयोग ऐसी अपेक्षा को अनुज्ञापिकाओं को अधिसूचित करता है।

(h) प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं, विवरण अनुज्ञापन की लागू होने के तीन माह के भीतर आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि हेतु कारीबार योजना प्रस्तुत करेगा और उसका वार्षिक रूप से अद्यतन करेगा। कारीबार योजना में वर्ष वार माह वृद्धि, विनिर्दिष्ट कार्रवाई योजना सहित वर्ष वार विवरण में होने वाली होने में कमी का प्रस्ताव, अन्तर फिस बिन्दुओं को मापने के लिए भीतरिय योजना, विनिर्माण योजना, पूर्व हानियों का उपचार अथवा पुनर्संरचना योजना, लागत कटौती योजना, संभावित लाभ हानि लेख, संभावित तुलन मात्र, संभावित रिकॉर्ड उपलब्धता और संभावित महत्वपूर्ण वित्तीय प्रायल (पेरामेटर्स) सम्मिलित होंगे।

(iii) आयोग प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही पर यह अपेक्षा करेगा कि वह पूर्व वित्तीय वर्ष की योजना के क्रियान्वयन की तुलना में, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित योजना, को सूचित करे।

४ विनिर्माण (i) प्रारम्भ कारीबार में होने वाले विनिर्माण हेतु आयोग द्वारा समय समय पर जारी विनियमों, विधा निर्देशों और आदेशों का प्रारम्भ अनुज्ञापिकाओं सम्यक रूप

में पालन करेगा ।

(2) राज्य में दक्ष, समानित व गितव्ययी पारेषण पणाली को बनाने, रख रखाव व चलाने हेतु पारेषण अनुज्ञापिधारी कर्तव्यबोध के अनुसार पद्धति विनियोजन करेगा ।

(3) पारेषण अनुज्ञापिधारी विनियम 7 के उप-विनियम (b) के अन्तर्गत संबंधित अवधि के लिए विनियोजन योजना के विवरण सहित कसोबार योजना को विनियोजन योजना के रूप में आयोग के समक्ष मन्जूरी हेतु प्रस्तुत करेगा । पारेषण अनुज्ञापिधारी आयोग का समाधान करते हुए यह प्रदर्शित करेगा कि -

(क) पारेषण पणाली में विनियोजन योजना में दी गई विनियोजन की आवश्यकता है,

(ख) पारेषण अनुज्ञापिधारी ने ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई पारेषण पणाली आसितियों का विनियोजन करने के लिए या अजित करने के लिए प्रस्तावों के समस्त लाभप्रद विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी पणाली और पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण कर लिया है ।

(4) पारेषण अनुज्ञापिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अन्त तक निम्न सूचना देगा -

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान कियान्वयन में ली जाने वाली विनियोजन स्कीम के ब्यौरे सहित वार्षिक विनियोजन योजना ; और

(ख) पूर्व वर्ष के लिए आयोग द्वारा मन्जूर विनियोजन योजना के सम्बन्ध में वास्तविक कियान्वयन की तुलना के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विनियोजन स्कीम के कियान्वयन में की गई प्रगति ।

(5) पारेषण अनुज्ञापिधारी आयोग द्वारा उप-विनियम (3) के अधीन मन्जूर विनियोजन योजना में समाविष्ट न की गई मुख्य विनियोजन योजनाओं को, आयोग की पूर्व मन्जूरी के बिना, हाथ में नहीं लेगा और ऐसी मन्जूरी लेने हेतु पारेषण अनुज्ञापिधारी आयोग का समाधान करते हुए उप विनियम (3) में वर्णित तत्त्वों को प्रदर्शित करेगा ।

(6) पारेषण अनुज्ञापिधारी आयोग द्वारा यथा-निर्दिष्ट पारदर्शी विविदा प्रक्रिया अपना

कर उपरकर, सामग्री और/या मुख्य विनिधान से सम्बन्धित सेवाओं के उपपान हेतु निविदाएँ आमंत्रित कर उन्हें अन्तिम रूप देगा। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के परामर्श से

- (i) सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण पब्लिकनीय नीति तथा पक्षिका, जिसमें विभिन्न कार्यवाहियों, मन्तव्यों, कय आदेश देने, रूपदंगी सारणी तथा भूगतान इत्यादि की कार्यसूची भी सम्मिलित है, इस प्रकार से रूपवाहित है कि मन्तूर मानकों तथा संदर्भिकाओं के निष्ठापूर्वक कर्मान्वयन एवं अनुपालन को सुकर बनाने हेतु तत्तित समय पर तत्तित कोटि का आवश्यक विनिधान हो सके,
- (ii) संदर्भिक मूल्य निर्धारण करेगा तथा वित्तीय नियन्त्रण रखने हेतु विकेंद्रित कय के लिए दर संविदा निर्णयित करेगा तथा ऐसे विकेंद्रित कय के बारे में अधिकतम वित्तीय अनुपात प्राप्त करने के लिए तालिका नियन्त्रण करेगा।

(7) इस विनियम के पयोजन हेतु "मुख्य विनिधान" से पारेषण सुविधाओं के अर्जन हेतु या उरागें नियोजित विनिधान अभिप्रेत है, जिसकी लागत जब समस्त कार्यसम्पादन में अन्य सभी विनिधानों या अर्जनों (यदि कोई हो), के रूप में संकलित की जाए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर विशेष शर्तों में यथा अन्तर्विष्ट लागू या आयोग द्वारा समय-समय पर अन्यथा साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित शर्तों के बराबर या उससे अधिक हो।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उप-विनियम (3) और (4) में आने वाले पारेषण कारोबार के अतिरिक्त अन्य कारोबार में निवेश करने का अधिकार होगा, परन्तु तैरिफ के अवधारण हेतु ऐसे विनिधान पर विचार करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग का समाधान करेगा कि ऐसे पारेषण कारोबार के लिए विनिधान आवश्यक था और यह विनिधान दक्षपूर्ण, समन्वित और मितव्ययी ढंग से किया गया है।

(9) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग को "पत्याशित (सम्भावित) राजस्व गणना" के साथ आयोग द्वारा मन्तूर परियोजनाओं को समाविष्ट करते हुए वार्षिक विनिधान योजना के मुख्य बिन्दु एवं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आयोजित अन्य सभी परियोजनाओं को, जिसमें आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है आयोग को, मन्तूरी हेतु परतुत करेगा और उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त विनिधान योजना के अनुसार निवेश करेगा

परन्तु यदि किसी अनपेक्षित आकस्मिताओं के कारण वार्षिक विनिधान योजनाओं में

सूचीबद्ध परियोजना के भीतर निधियों के पुनराबंटन की आवश्यकता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसा पुनराबंटन इस प्रकार कर सकता है जब तक कि वैयक्तिक परियोजना के सम्बन्ध में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू विशिष्ट शर्तों में या अन्यथा आयोग के साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्धारित राशि से अधिक न हो। पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे पुनराबंटन को आयोग को निवेश करने के 7 दिनों के भीतर, सम्यक् रूप से सूचित करेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को परियोजना में ऐसा निवेश, जो वार्षिक विनिधान योजना में सम्मिलित नहीं है, करना अपेक्षित है, तो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यदि यह मुख्य विनिधान नहीं है और उप-विनियम (8) में दी गई की शर्तों के अनुरूप है, ऐसा कर सकता है ।

9. परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण.— (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपयोजित तथा अनुपयोजित परिसम्पत्तियों, अनुत्पादक तथा अलाभकर परिसम्पत्तियों को पृथक्कृत करेगा और अनुत्पादक तथा अलाभकर परिसम्पत्तियों की परिसम्पत्ति-सूची तैयार करेगा ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी "स्थिर परिसम्पत्ति-रजिस्टर" तैयार करेगा और चालू पूंजीगत संकर्म खाते में प्रतिबिम्बित राशि का समय-समय पर अन्वेषण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि पूरे किए गए संकर्म, यथाशीघ्र पूर्ण होने पर "स्थिर परिसम्पत्ति-रजिस्टर" में अंतरित कर दिये गए हैं ।

(3) आयोग या तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से स्वतन्त्र अभिकरण से परिसम्पत्तियों की आस्तित्व जाँच करवाने की उपेक्षा कर सकेगा या स्वयं उक्त जाँच अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर करेगा, जो समेकित राजस्व गणना में अनुज्ञात होगा ।

(4) इस विनियम में उपबंधित शर्तों के पालन के सिवाए, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, एकल संव्यवहार या संबन्धित संव्यवहार के समूह में किसी ऐसी आस्ति, जिसका प्रस्तावित अंतरण के समय वही मूल्य जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू आयोग द्वारा विशेष शर्तों के अधीन या अन्यथा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित राशि से अधिक हो, के प्रचालन नियंत्रण का अंतरण या त्यजन नहीं करेगा ।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा उप-विनियम (4) के अधीन तय मूल्य से अधिक के मूल्य की आस्ति के प्रचालन नियंत्रण का आयोग को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना अंतरण या त्यजन नहीं करेगा । अनुज्ञप्तिधारी समस्त सम्बन्धित तथ्यों को लिखित नोटिस के

माध्यम से आयोग के समक्ष प्रकट करेगा। आयोग नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संव्यवहार के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है, और सामान्यतः पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर, और जहाँ आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त अतिरिक्त जानकारी माँगी जाती है, वहाँ आवेदन दायर करने के 60 दिनों के भीतर ऐसी शर्तों या उपांतरणों के अध्यधीन अंतरण व्यवस्था जैसी समुचित समझी जाए, को मन्जूर कर सकता है या आयोग अपने लिखित आदेश द्वारा कारणों को बताते हुए इसे न मन्जूर कर सकता है।

(6) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उप-विनियम (5) के अधीन दिए गए किसी नोटिस में वर्णित किसी के प्रचालन नियंत्रण का अंतरण या त्यजन कर सकेगा जहाँ कि—

- (क) आयोग लिखित में यह पुष्टि करता है कि वह प्रचालन नियन्त्रण का अंतरण या त्यजन ऐसी शर्तों के अध्यधीन है जैसी कि आयोग द्वारा अधिरोपित की जाएँ; या
- (ख) आयोग उप-विनियम (5) के अधीन दिये गए नोटिस की अवधि के भीतर प्रचालन नियंत्रण के ऐसे अंतरण या त्यजन पर कोई आपत्ति को लिखित में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित नहीं करता है और अंतरण पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया से प्रभावी होता है।

(7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी आस्ति पर प्रचालन नियंत्रण का अंतरण या त्यजन करभी सकेगा, जहाँ कि—

- (क) आयोग ने निम्न के सम्बन्ध में सामान्य सहमति (चाहे शर्तों के अध्यधीन हो या न हो) अंतर्विष्ट करते हुए इस विनियम के प्रयोजन हेतु निर्देश जारी कर दिये हों,—

- (1) विनिर्दिष्ट विवरण का संव्यवहार, और/या
- (2) विनिर्दिष्ट विवरण की आस्ति के प्रचालन नियंत्रण का अन्तरण या त्यजन और/या
- (3) प्रचालन नियन्त्रण के अन्तरण या त्यजन शर्तों के अनुसार है जिसके अधीन सहमति है, या

- (ख) प्रचालन नियंत्रण का अन्तरण या त्यजन किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके

अधीन अपेक्षित है; या

(ग) प्रश्नगत आस्ति किसी अन्य कारोबार के सम्बन्ध में जो अन्नयतः या प्राथमिक रूप से पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित और उपयोग में लाई गई थी और इस से भूमि में कोई विधिक या हितकारी हित नहीं होता है या पारेषण प्रणाली का कोई भाग नहीं है या अन्यथा अनुज्ञप्त कारोबार के लिए अपेक्षित आस्ति नहीं है ।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उसकी विनिधान आवश्यकताओं के वित्तपोषण को सुकर बनाने के साधन के रूप में आस्तियों का उपयोग निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए करने का हकदार होगा, जिसमें ऋण वित्तपोषण और प्राप्यों का प्रतिरक्षण सम्मिलित है:-

(क) यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत करार के प्रारम्भ की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व ऐसे अनुबन्ध के बारे में आयोग को सूचित करेगा;

(ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आस्तियों के ऐसे उपयोग में, विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रीति से कार्य करता है; और

(ग) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली में आस्तियों पर प्रचालन नियंत्रण प्रतिधारित करता है ।

(9) इस विनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी आपातकालीन अवस्था में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी आस्ति का इस शर्त पर अन्तरण कर सकता है कि ऐसे किसी संव्यवहार के अव्यविहत पश्चात् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी संव्यवहार की आपातकालीन प्रतिस्थितियों के विस्तृत तथ्यों और किए गए संव्यवहार का ब्यौरा दे कर आयोग की कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा । यह पारेषण अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि वह आस्ति के अन्तरण के लिए उत्पन्न आपातकालीन आवश्यकता को आयोग की तुष्टी के अनुसार सिद्ध करे ।

10. अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान.— (1) ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसे कि आयोग निर्दिष्ट करे, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2005 या विशेष शर्तों में उल्लिखित प्रारम्भिक और सामायिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा ।

(2) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शोध्य तिथि तक उप-विनियम (1) के अधीन किसी

भी देय शुल्क का भुगतान आयोग को करने में असफल रहता है, वहाँ -

- (क) अन्य दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी शेष देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज बकाया रकम पर देने का दायी होगा। ब्याज उस दिन के पश्चात् की अवधि पर देय होगा जिसको कि रकम शोध्य होती है और उस दिन को समाप्त होगा जिस तारीख को आयोग को भुगतान किया जाता है ; तथा
- (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगातार बकाया होने की स्थिति में आयोग पारेषण अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित कर सकता है ।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ के लिए संकलित राजस्व के अवधारण में व्यय के रूप में इस विनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए गए किसी भी शुल्क को हिसाब में लेने का हकदार होगा :

परन्तु इस में देरी से किए गए भुगतान पर संदत्त ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

11. प्रतिसंहरण की शर्तें.— (1) अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों और उसके अधीन बने विनियमों के अधीन, आयोग किसी भी समय, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाई प्रारम्भ कर सकेगा और यदि ऐसी कार्यवाईयों में प्रतिसंहरण के आधारों और लोक हित से उसका समाधान हो जा जाता है, तो वह निम्नलिखित दशा में पारेषण अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा, अर्थात्,—

- (क) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग की राय में अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में अपेक्षित कोई भी बात को करने में जानबूझकर और विलंबित व्यतिक्रम करता है ;
- (ख) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन से अनुज्ञप्ति अभियुक्तः प्रतिसंहत हो जाए ;
- (ग) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति में नियत अवधि के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि जिसे आयोग ने प्रदान किया हो, के भीतर—

(1) आयोग को यह दर्शाने में असफल रहता है कि अनुज्ञप्ति में उसके

ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ; या

(2) अनुज्ञप्ति में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप करने या फीस या अन्य प्रभार का संदाय करने में असफल रहता है;

(घ) जहाँ आयोग की राय में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूर्णतः और दक्षता से निभाने में असमर्थ रहता है ; और

(ङ) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के सभी विनियमों, कोडों, और मानकों और आदेशों व निर्देशों के पालन में असफल रहता है या अन्यथा ऐसा कृत्य करता है, जिससे अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य आधारों पर पारेषण अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरणीय हो जाए ।

(2) जहाँ उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो आयोग आवेदन प्राप्त होने पर या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुज्ञप्ति को पूर्ण रूप से या उसके पारेषण क्षेत्र के किसी भाग के लिए ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझता हो, प्रतिसंहत कर सकेगा ।

(3) पारेषण अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने से पूर्व, आयोग, यदि उसकी राय में आवश्यक हो, मामला राज्य सरकार को भेज सकता है और पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिए सहमत होगा ।

12. अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.— (1) आयोग, यदि लोकहित में आवश्यक समझता हो, अधिनियम की धारा 18 के अधीन अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों में परिवर्तन और संशोधन निम्न शर्तों पर कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए आवेदन किया हो, वहाँ पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदन की सूचना को आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से और विशिष्टियों सहित प्रकाशित करेगा ;

(ख) किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प के या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के अधिभोग में/के किसी भवन या स्थान के सभी या किसी भाग

को समाविष्ट करने वाले कार्य क्षेत्र में परिवर्तन या उपांतरण का प्रस्ताव करने वाले आवेदन की दशा में, कोई भी परिवर्तन या उपांतरण केवल केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा ;

(ग) जहाँ किसी अनुज्ञप्ति में किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से अन्यथा कोई परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया हो, आयोग ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन को ऐसी विशिष्टियों सहित और ऐसी रीति से प्रकाशित करवाएगा, जैसे आयोग उचित समझे ;

(घ) ' आयोग कोई भी परिवर्तन या संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार न कर लिया हो ।

13. विवाद समाधान.— (1) आयोग को अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1)

के खण्ड (घ) के साथ पठित धारा 158 और आयोग के विनियमों के अनुसरण में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनी के बीच विवाद को न्यायनिर्णित करने या हल करने के लिए मध्यस्थता करने अथवा किसी व्यक्ति को माध्यस्थता के रूप में मनोनीत करने का अधिकार होगा ।

(2) आयोग, यथास्थिति, स्वयं उप-विनियम (1) के अधीन विवादों की माध्यस्थता कार्यवाई को प्रारम्भ और संचालित कर सकता है या विवादों को आयोग के कारोबार संचालन विनियमों के अनुसार अन्य की मध्यस्थता के लिए निवेदित कर सकता है ।

14. पारेषण योजना एवं सुरक्षा मानक, पारेषण प्रचालन मानक.— (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पारेषण प्रणाली के प्रचालन की एक योजना बनायेगा तथा प्रचालित करेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बनाई गई प्रचालित तथा सम्पोषित पारेषण प्रणाली ग्रिड कोड तथा सम्पूर्ण निष्पादन मानकों के अनुसार एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी पारेषण करने में समर्थ है ।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उस अवधि में जैसे आयोग निर्दिष्ट करे,—

(क) विद्युत प्रदाय योजना एवं सुरक्षा मानक तथा विद्युत प्रदाय प्रचालन मानक पूरा करने ;

(ख) सुरक्षा मानक अधिकथित करने की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सुरक्षा योजना अपनाता है ताकि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित और आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत पारेषण विश्वसनीयता तथा गुणवत्ता के स्तरों को पूरा करे ;

(ग) प्रचालन मानकों का स्तर, आयोग द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित प्रचालन मानकों के अनुसार सुनिश्चित करने; की व्यवस्था करेगा ।

(3) (क) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उस अवधि में जैसे आयोग, विशिष्ट शर्तों में या अन्यथा निर्दिष्ट करे, अपनी पारेषण प्रणाली वे विद्यमान योजना एवं सुरक्षा मानकों तथा प्रचालन मानकों; और उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित विद्यमान योजन एवं सुरक्षा मानकों तथा प्रचालन मानकों को जिनका पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पालन कर रहा है, आयोग को प्रस्तुत करेगा । ऐसे विद्यमान मानक, उन उपान्तरणों सहित जो आयोग निर्दिष्ट करे, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नए मानक आयोग द्वारा अनुमोदित न हो जाएं ।

(ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, उस अवधि में जैसे आयोग विशिष्ट शर्तों में या अन्यथा निर्दिष्ट करे, प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड एवं ऐसे व्यक्ति जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएँ, के परामर्श से, अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण योजना एवं सुरक्षा मानकों तथा पारेषण प्रचालन मानकों और प्रचालन मानकों के प्रस्ताव, जो इन विनियमों के अनुसार हों, तैयार करेगा एवं आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा ।

(ग) पारेषण योजना एवं सुरक्षा मानक, पारेषण प्रचालन मानक तथा प्रचालन मानक, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस विनियम के अनुसार प्रस्तुत किए जायें, ऐसे उपान्तरणों सहित जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे ।

(4) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उसके दायित्वों के नियम भंग करने हेतु उत्तरदायी नहीं माना जाएगा यदि वह पारेषण योजना एवं सुरक्षा मानकों या पारेषण प्रचालन मानकों के उपबन्धों की पूर्ति में अपरिहार्य घटनाओं के कारण असफल रहे, वशर्त कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ने यथासंभव यथास्थिति पारेषण योजना एवं सुरक्षा के मानकों या पारेषण प्रचालन मानकों के पारिपालन का समुचित प्रयास किया हो ।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता,

राज्य उपयोगिता क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जैसे कि आयोग आदेशित करे के परामर्श से ऐसे प्रत्येक अवसर पर जब ग्रिड कोड को पुनरीक्षित किया जाए, इन मानकों एवं उनके क्रियान्वयन को पुनरीक्षित करेगा । ऐसे किसी पुनरीक्षण के अनुकूल में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को प्रेषित करेगा -

- (क) ऐसे पुनरीक्षण के परिणामों पर एक रिपोर्ट;
- (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा समय-समय पर ऐसे दस्तावेजों का प्रस्तावित पुनरीक्षण (ऐसे पुनरीक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में) ;
- (ग) प्रदायकर्ताओं, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड, तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों जैसे कि आयोग परामर्श की प्रक्रिया के दौरान आदेशित करे, से प्राप्त (पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अस्वीकार की गई सहित) कोई लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियाँ :

परन्तु यह कि अधोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से आवेदन प्राप्त होने पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मानकों तथा उनके क्रियान्वयन के पुनरीक्षण के उत्तरदायित्वों से उस सीमा तक मुक्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को जारी निर्देशों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(6) लिखित अभ्यावेदनों तथा आपत्तियों के दृष्टिगत तथा ऐसे अग्रिम परामर्श के परिपालन में (यदि कोई हो) जैसा कि आयोग उचित समझे, आयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से मानकों के पुनरीक्षण हेतु अपेक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकता है, जैसा निर्देशों में विनिर्दिष्ट किया जाए । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्देशित पुनरीक्षण सम्यक् रूप में करवाएगा ।

(7) प्रत्येक वित्त वर्ष के अन्त में, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी 3 माह की अवधि में पारेषण प्रणाली का पूर्व वर्ष में कार्य सम्पादन दर्शाते हुए एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यदि आयोग द्वारा अपेक्षित हो, अपनी रिपोर्ट की संक्षेपिका इस रीति से प्रकाशित करेगा जो आयोग द्वारा निर्धारित की जाए । इस रिपोर्ट की प्रतियाँ ऐसे सभी व्यक्तियों को छाया प्रति की कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जो इस हेतु आवेदन दें ।

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के अनुरोध पर आयोग को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा जो आयोग को इस विनियम के अधीन या प्रयोजन के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के

कर्तव्यों एवं दायित्वों के पर्यवेक्षण हेतु आवश्यक समझे ।

15. ग्रिड कोड.— (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी लागू राष्ट्रीय ग्रिड कोड, क्षेत्रीय ग्रिड कोड तथा राज्य ग्रिड कोड का सम्यक् रूप में पालन करेगा ।

(2) राज्य ग्रिड कोड अधिनीयम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन आयोग द्वारा समय-समय पर बनाया जाएगा ।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता, क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जैसे कि आयोग आदेश दे, के परामर्श से समय-समय पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के प्रचालन से जितना सम्बन्धित है, ग्रिड कोड एवं उसके क्रियान्वयन को पुनरीक्षित करेगा । ऐसा पुनरीक्षण कम से कम तीन वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए । ऐसे किसी पुनरीक्षण के पश्चात् पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग तथा राज्य पारेषण उपयोगिता को प्रेषित करेगा :—

- (क) ऐसे पुनरीक्षण के परिणामों पर एक रिपोर्ट;
- (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिसे वह युक्तियुक्त समझता हो, समय-समय पर ग्रिड कोड का प्रस्तावित पुनरीक्षण;
- (ग) परामर्श की प्रक्रिया के दौरान पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियाँ ।

16. संयोजन तथा प्रणाली का प्रयोग.— (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा खुली पहुँच के लिए विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार, अपनी प्रणाली में पर्याप्त पारेषण क्षमता की उपलब्धता होने पर और उपभोक्ताओं द्वारा समस्त अनुज्ञात प्रभार, जिनमें वितरण प्रभार व जहाँ लागू हो अधिभार भी हैं, के सन्दाय करने को सहमत होने पर उपभोक्ताओं को अपनी पारेषण प्रणाली तक अविभेदकारी खुली पहुँच प्रदान करने हेतु व्यवस्था करेगा ।

(2) किसी व्यक्ति को जो पारेषण प्रणाली का उपयोग करना चाहता है संयोजन प्रदत्त करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उस व्यक्ति से पारेषण प्रणाली से संयोजन के लिए अथवा किसी विद्यमान संयोजन में उपांतरण हेतु करार निष्पादित करने के लिए प्रस्ताव करेगा और उक्त प्रस्ताव में निम्न के लिए उपबन्धित किया जाएगा :—

- (क) अपेक्षित संयोजन, जिसमें मीटर लगाने भी सम्मिलित हैं, के लिए आवश्यक संकर्मों

का कार्यान्वयन करेगा ;

- (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने के आवश्यक सकर्मों का कार्यान्वयन करना ;
- (ग) आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट संयोजन प्रमारों को सन्दाय ; तथा
- (घ) समापन की तारीख तथा प्रति-स्थितियों के अनुसार अन्य समुचित शर्तें ।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी यथासाध्य शीघ्रता से प्रणाली के प्रत्याशियत उपभोक्ताओं को उप-विनियम (1) तथा (2) की शर्तों पर करार निष्पादित करने के लिए प्रस्ताव करेगा । पारेषण अनुज्ञप्तिधारी करार प्रस्तावित करने या करार करने हेतु बाध्य नहीं होगा यदि :-

- (क) पारेषण प्रणाली में पर्याप्त क्षमता उपलब्ध नहीं है :

परन्तु उक्त क्षमता की उपलब्धता का होना या न होना राज्य पारेषण उपयोगिता की अवधारणा के अध्वधीन होगा तथा उस दशा में जब उक्त अवधारणा पर कोई विवाद उठता है तो आयोग का विनिश्चय मान्य होगा;

- (ख) जो अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के खण्डन में हो ;
 - (ग) जो पारेषण कारोबार को लागू सुरक्षा या मानकों से सम्बन्धित नियमों या विनियमों, जिन में प्रचलित नियम भी आते हैं; के खण्डन में हो ;
 - (घ) जो ग्रिड कोड के खण्डन में हो ,
 - (ङ) जिस व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाए वह समय-समय पर लागू ग्रिड कोड के उस व्यक्ति पर प्रयुक्त होने की सीमा तक, परिपालन हेतु सहमत न हो ; या
 - (च) जिस व्यक्ति द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया हो वह लागू प्रभारों, अधिभारों, आयोग द्वारा यथा अवधारित पारेषण प्रणाली में विद्युत क्षति समायोजन न करे ।
- (4) यदि ऐसी अवधि जो आयोग को इस प्रयोजन हेतु विवेकपूर्ण लगे, पारेषण

अनुज्ञप्तिधारी जो निवेदन करने पर पारेषण प्रणाली के प्रत्याशित उपयोक्ता से करार करने में असमर्थ रहता है, तो आयोग ऐसे प्रत्याशित उपयोक्ता के आवेदन पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी तथा उक्त व्यक्ति के बीच विवाद के प्रावधानों का समाधान करेगा तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा किये गये समाधान के अनुसार ऐसा करार करेगा एवं उसका क्रियान्वयन करेगा ।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक आधार पर अगले 5 वर्षों का, प्रत्येक वर्ष के बारे में आदर्श नियोजन मानक के अनुसार सर्किट क्षमता, विद्युत प्रवाह तथा पारेषण प्रणाली पर भार के पूर्वानुमान का पत्रक तैयार करेगा तथा आयोग को प्रस्तुत करेगा, साथ ही :-

- (क) ऐसी अन्य जानकारी जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रणाली का उपयोग करना चाहता है कि जब ऐसी प्रणाली से संयोजन तथा उपयोग किया जाए तब उपलब्ध अवसरों की पहचान तथा मूल्यांकन हेतु आवश्यक होगी ;
- (ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किया गया विवरण जिसमें उसकी पारेषण प्रणाली के उन भागों पर उसके अभिमत दर्शाये गए हों जो नये संयोजन तथा अतिरिक्त मात्रा में विद्युत पारेषण हेतु सर्वोत्तम हों ।

(6) किसी व्यक्ति या प्रदायकर्ता द्वारा, जो पारेषण प्रणाली का उपयोग करना चाहते हो, के निवेदन पर पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे विवरण पत्रक तैयार कर अद्यतन करेगा जिसमें अद्यतन उपलब्ध आंकड़े शामिल किये जायेंगे, विशेष रूप से ऐसी सुविधा को शामिल किया जाएगा। जिसका पारेषण प्रणाली के उपयोग तथा उससे संयोजन हेतु अनुरोध किसी अन्य व्यक्ति या प्रदायकर्ता द्वारा किया गया हो ;

(7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी दिये गये/भेजे गये विवरण पत्रक का उचित मूल्य किसी व्यक्ति से जो प्रणाली का उपयोग करना चाहता हो, वसूल कर सकेगा ;

(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी समस्त आवश्यक गतिविधियों को सम्पादित करने हेतु सक्षम होगा जो अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार से सम्बन्धित हो तथा आवश्यक हो । इसमें अनुज्ञप्त पारेषण कारोबार हेतु समुचित संचार-जाल की स्थापना एवं प्रचालन आवश्यक होगा जिससे ऐसी सूचना तकनीक का क्रियान्वयन किया जा सके (रिमोट) जो दूरस्थ मीटरिंग आदि, पर आधारित हो ।

17. सम्भावित राजस्व गणना और टैरिफ.- (1) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में,-

- (क) विश्वसनीय और सही लागत तथा व्यय के आधार आँकड़े बनाएगा, ताकि

- . स्टेक-होल्डर, कुछ हद तक विनियामक निश्चयता से, टैरिफ अवधारण हेतु विवेकपूर्ण आधार पाने के लिए इन लागतों तथा व्यय पर संकेंद्रित कर सकें;

(ख) प्रदाय की सीमान्त लागत, जिसमें बोल्टा स्तरों की अन्तरीय सीमान्त लागत भी सम्मिलित है, का अध्ययन करवाएगा;

(ग) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सेवा गुणवत्ता सुधारने, राजस्व बढ़ाने तथा पारेषण क्षति घटाने के लिए अनिवार्य ऊर्जा संपरीक्षा करवाएगा, अपनी पारेषण प्रणाली का नियोजन एवं प्रबन्ध करेगा और विद्यमान मानव संसाधनों को सुव्यवस्थित करेगा; वैज्ञानिक अभियान्त्रिकी संसाधन प्रबन्धन के माध्यम से कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु संरचनात्मक कुटनीति, प्रणाली एवं हुनर का सुधार तथा आधुनिकीकरण करवाएगा।

(2) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम, आयोग के विनियमों, टैरिफ के नियमों व शर्तों व आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य मार्गदर्शन, आदेशों और निर्देशों के उपबन्धों के अनुसार प्रभारों, जिसे उसे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, से सम्भावित राजस्व की गणना करेगा।

(3) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सम्भावित राजस्व गणना और अधिनियम की धारा 61 के अधीन आयोग के टैरिफ अवधारण हेतु विनियमों में उपबंधित रीति में तथा उनके अनुसार टैरिफ प्रस्ताव का आवेदन देगा।

(4) जब तक विशेष शर्तों या आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्देश द्वारा अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी प्रति वर्ष, 30 नवम्बर तक आयोग को—

(क) अधिनियम और उसके अधीन आयोग द्वारा, समय-समय पर जारी, विनियमों, दिशा-निर्देशों और आदेशों के उपबन्धों के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष की सम्भावित संकलित राजस्व और सेवा लागत (जिसमें लागत वित्तपोषण और अकिवटि पर इसकी सम्भावित आय सम्मिलित है) का विस्तृत विवरण देगा;

(ख) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित वार्षिक निवेश योजना के विवरण और जिसे पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा पहले से ही ऐसे निवेश

हेतु अनुमोदित योजनाओं, यदि कोई हों, के उचित संदर्भ में, आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व आवश्यकता के अधीन लाने का इच्छुक हो, का विनिर्दिष्ट निवेश योजना विवरण देगा;

पारेषण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अपने प्रत्येक अनुज्ञप्त और अन्य कारोबार के बारे में इसमें इस से पूर्व संदर्भित कथन तथा निवेश योजना का विवरण अलग-अलग देगा।

(5) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, संभावित राजस्व गणना या अन्य किसी ऐसे समय और आवर्तन में, आयोग जैसे विशेषतः अनुज्ञात करे, टैरिफ प्रस्तावों और आयोग द्वारा अनुमोदित विद्यमान टैरिफ में संशोधन, जो पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकताओं से मेल खाता हो, का आवेदन देगा।

(6) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ से वसूल की जाने वाली राशि वह राशि होगी जिसे आयोग अधिनियम के और आयोग के विनियमों के उपबन्धों के अनुसार अनुमोदित करे।

(7) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 39 तथा 40 में यथा उपबन्धित अधिभार की राशि, यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस दशा में जब उपभोक्ता को विद्युत पारेषण आयोग द्वारा निदेशित किया गया हो, वसूल की जानी अनुज्ञात हो, सम्बन्धित वितरण अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को, अधिनियम तथा आयोग के विनियमों व निर्देशों के अनुसार, टैरिफ में संशोधन हेतु आवेदन दे सकता है।

18. राज्य पारेषण उपयोगिता को लागू सामान्य शर्तें.— सिवाये उन उपबन्धों के जो पारेषण अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण तथा अधिनियम की धारा 32 के अधीन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के कृत्यों और अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन गतिविधियों से संबन्धित हैं, इन विनियमों के सभी उपबन्ध राज्य पारेषण उपयोगिता को लागू होंगे।

19. विविध.—(1) इन विनियमों की और उनकी शर्तों के बारे में व्याख्या से सम्बन्धित उठने वाले सभी विवादक आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे और ऐसे विवादकों पर आयोग का विनिश्चय केवल अधिनियम की धारा 111 के अपील करने के अधिकार के अध्यक्षीन अन्तिम होगा।

(2) आयोग पारेषण अनुज्ञप्ति मन्जूर करते समय, या तो अनुज्ञप्ति मन्जूर करने वाले आदेश में या किसी विनिर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होने वाली विशेष शर्तों द्वारा इन विनियमों के किसी भी लागू उपबन्ध का अधित्यजन या उपान्तरण कर सकता है ।

20. समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू उपबन्ध.— अधिनियम लागू होने पर पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सभी आवेदकों, और अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पाँचवे परन्तुकों के अधीन सभी समझे गए पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, पर एतद्वारा दी गई सामान्य शर्तें लागू होंगी ।

21. कठिनाईयों दूर करना.—(1) आयोग, अधिनियम के अध्याधीन रहते हुए, समय-समय पर, इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में जिसके लिए आयोग को इन विनियमों द्वारा और उनसे सम्बन्धित, प्रासंगिक या आनुषंगिक मामलों में निर्देश देने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश अथवा पद्धति निर्देश दे सकता है ।

(2) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी समुचित कार्रवाई करने या करने को मानने के लिए कह सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन लगे ।

(3) इस विनियम के अधीन कोई भी आदेश इन विनियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगा और उसके जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

22. निरसन और अपवाद.— (1) इन विनियमों में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 या अन्य किसी विधि के अधीन पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए जारी सामान्य या विशेष शर्तों को जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व लागू हों, एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पारेषण अनुज्ञप्ति की निरस्त सामान्य या विशेष शर्तों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या अभिप्रेत कार्रवाई, जब तक इन विनियमों के उपबन्धों से अनसंगत न हो, के इन विनियमों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया गया समझा जाएगा ।

(3) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व जारी पारेषण अनुज्ञापति की विशेष शर्तें और निर्देश (जिसमें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन सुनवाई के दौरान टैरिफ आदेश, 2001-02 के अर्थात् 7 में उल्लिखित निर्देश सम्मिलित हैं), जो इन विनियमों के उपबन्धों से अनसंगत नहीं हैं, उस अवधि तक लागू रहेंगे जब तक के लिए ऐसी सामान्य या विशेष शर्तें या निर्देश जारी किए गए थे ।

शिमला, 30 सितम्बर, 2005

संख्या एच० पी० इ० आर० सी/412.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003, (2003 का 36) की धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) सहित पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस द्वारा आयोग की अधिसूचना संख्या एच.पी.इ.आर.सी/381 दिनांक 8-6-2004 द्वारा बनाये तथा आयोग की अधिसूचना संख्या एच.पी.इ.आर.सी/381 दिनांक 22-2-2005 द्वारा संशोधित किए गए हिमाचल प्रदेश इलैक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन (जनरल कण्डीशनज आफ डिस्ट्रीब्युशन लाईसेंस) रेगुलेशनज, 2004, किन्हीं कारणों से जिनका हिन्दी पाठ प्रकाशित नहीं हो पाया है, का निम्न हिन्दी पाठ प्रकाशित करता है:—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञापति की सामान्य शर्तें) विनियम, 2004 है !

(2) ये विनियम 10 जून, 2004 से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) “अधिनियम” से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;

(2) “लेखा विवरण” से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) में दिए गए विवरण के अनुसार अनुज्ञप्त कारोबार का लेखा विवरण, अभिप्रेत है जिसमें लाभ-हानि लेखा, तुलन-पत्र और संसाधनों का तथा निधियों की प्रायोज्यता का टिप्पणियों सहित विवरण तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निदेशित अन्य ऐसे विवरण व व्योरे समाविष्ट होंगे । यदि वितरण अनुज्ञापतिधारी अनुज्ञप्त कारोबार के अतिरिक्त किसी अन्य कारोबार अथवा गतिविधि

में संलग्न रहता है तो लेखा विवरण आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञापिधारी के अन्य कारोबार के निपटारे हेतु बनाए गए विनियमों के अनुपालन -- स्वरूप होने चाहिए तथा उसमें राजस्व, लागत, आरितयों, दायित्व, आरक्षित धन या प्राक्धान को, जो या तो --

(क) किसी अनुज्ञप्त कारोबार से भिन्न, किसी अन्य कारोबार पर प्रभार हो, या प्रभारित किया गया हो, उसा प्रभार के आधार के विवरण सहित, या

(ख) अनुज्ञप्त कारोबार और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अन्य कारोबार के सम्बन्ध में प्रभाजन या आबंटन द्वारा अवधारित हो; प्रभाजन या आबंटन के आधार के विवरण सहित, अलग से दर्शाया जाएगा ;

(3) "वार्षिक लेखे" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबन्धों और/अथवा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आयोग द्वारा निदेशित अन्य रीति से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किए लेखे अभिप्रेत हैं;

(4) "वितरण क्षेत्र" या "प्रदाय क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी में दिया गया वितरण क्षेत्र है, और जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को वितरण प्रणाली स्थापित, परिवर्तित और सम्पोषित करने और विद्युत प्रदाय करने का अधिकार है ;

(5) "संपरीक्षक" से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 224 से 234 -क या धारा 619, जैसे भी समुचित हो, के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी का पदधारित संपरीक्षक अभिप्रेत है;

(6) "प्राधिकृत" से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति, कारोबार या गतिविधि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुकों के अधीन प्रदत्त समझी गई या अधिनियम की धारा 13 और आयोग के विनियमों के अधीन में दी गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत, ;

(7) "आयोग" से हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, अभिप्रेत है ;

(8) "समझा गया अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम परन्तुकों के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(9) "वितरण" से वितरण प्रणाली के साधनों द्वारा विद्युत का चक्रण व पारेषण अभिप्रेत है ;

(10) "वितरण कारोबार" से प्राधिकृत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी प्रदाय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु वितरण प्रणाली को परिचालित तथा सम्पोषित करने के लिए वितरण कारोबार अभिप्रेत है;

(11) "वितरण कोड" से संयोजनों (कनैक्शनों) की बावत सभी महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं तथा वितरण प्रणाली के प्रचालन एवं प्रयोग हेतु आयोग के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया कोड अभिप्रेत है;

(12) "वितरण प्रणाली प्रचालन के मानक" से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के विनियमों में विनिर्दिष्ट वितरण प्रणाली के प्रचालन मानक अभिप्रेत है;

(13) "वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक" से आयोग के विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली की योजना और सुरक्षा की पर्याप्तता से सम्बन्धित मानक अभिप्रेत हैं ;

(14) " विद्यमान वितरण प्रणाली के प्रचालन मानक" से वितरण क्षेत्र में अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने की तारीख को यथा लागू वितरण प्रणाली के प्रचालन हेतु मानक अभिप्रेत हैं;

(15) "विद्यमान वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक" से वितरण क्षेत्र में अनुज्ञप्ति प्रदत्त करने की तारीख को लागू प्रणाली योजना व वितरण प्रणाली सुरक्षा मानक अभिप्रेत हैं;

(16) "अपरिहार्य घटना" से अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे की घटनाएँ अभिप्रेत हैं जिनमें भुकम्प, तुफान, बाढ़; आँधी, प्रतिकूल मौसम प्रभाव, युद्ध, आतंकवादी हमले, सिविल उपद्रव या अन्य ऐसी घटनाएँ जिन में विद्युत सुरक्षा से सम्बन्धित सुसंगत विधियों या विनियमों का उल्लंघन अंतर्निहित होता हो, किन्तु इन तक सीमित नहीं हैं;

(17) "जनित्र सैट" से विद्युत उत्पादन हेतु किसी संयंत्र या साधित्र अभिप्रेत है और इसमें जहां समुचित हो, एक या एक से अधिक उत्पादन उपकरण लगे उत्पादन केन्द्र भी सम्मिलित होंगे ;

(18) "अन्तःसंयोजन जनित्र सुविधाएँ" से जनित्र सैटों द्वारा पारेषण या वितरण प्रणाली तक पहुँच के लिए प्रयुक्त की गई विद्युत लाईनों, ट्रांसफार्मरों, बस-बारों, स्विचगियर, संयंत्र या साधित्र अभिप्रेत हैं;

(19) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड अभिप्रेत है और इस में अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड भी सम्मिलित है;

(20) "नियंत्री (होल्टिंग) कम्पनी" का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 में उसका है ;

(21) "अन्तरिम वितरण कोड" से अनुज्ञप्ति प्रदत्त होने की तारीख से ले कर उस दिन तक जब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए अधिनियम के अधीन वितरण कोड विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वितरण क्षेत्र में वितरण प्रणाली के प्रचालन हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनाई जाने वाली विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(22) "अन्तरिम ग्रिड कोड" से उस समय तक जब तक अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विद्यमान पद्धति और प्रक्रिया अभिप्रेत है ;

(23) "अनुज्ञप्त कारोबार" से वितरण अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत विद्युत वितरण व प्रदाय कारोबार अभिप्रेत है;

(24) "प्रमुख घटना" से अभिप्रेत है विद्युत के वितरण से जुड़ी ऐसी घटना जिसका परिणाम सेवा के विशिष्ट व्यवधान, उपकरणों को अधिक नुकसान या मानव जीवन को हानि या उत्प्लेखनीय चोट या आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट के रूप में हो, और इस में ऐसी अन्य घटना, जिसे आयोग स्पष्टतः प्रमुख घटना घोषित करे, भी सम्मिलित होगी ;

(25), "प्रचालन नियंत्रण" से अभिप्रेत है प्रचालन विनिश्चय को प्राधिकृत करने का अधिपत्य रखना, जैसे कि इकाईयों, सेवा लाईनों व उपस्करों का प्रवर्तन और उपयोगिकरण;

(26) "अन्य कारोबार" से अभिप्राय अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्त कारोबार से भिन्न अन्य

कारोबार से है;

(27) "निष्पादन मानक" से आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अनुसरण में अवधारित मानक अभिप्रेत हैं;

(28) "विशेष शर्तों" का अभिप्राय साधारण शर्तों के अतिरिक्त या उनसे भिन्न शर्तों से है, जो आयोग द्वारा किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के लिए विशेष रूप में निर्धारित की जाएं;

(29) "राज्य" से हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(30) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(31) "समनुषंगी" का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 4 में उसका है;

(32) "व्यापारिक कारोबार" से ऐसा प्राधिकृत कारोबार अभिप्रेत है; जो वितरण क्षेत्र में व्यापारी को प्रदत्त व्यापारिक अनुज्ञप्ति में अनुज्ञेय है;

(33) "व्यापारिक अनुज्ञप्ति" से विद्युत व्यापार के लिए अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदत्त की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(34) "व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी" से विद्युत व्यापारी अभिप्रेत है और इसमें समानुज्ञप्तिधारी जो अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्राधिकृत है, भी आता है ;

(35) "अंतरण" में विक्रय, विनिमय, दान, पट्टा, अनुज्ञप्ति, ऋण, प्रतिभूतिभरण, बन्धक, अनुज्ञप्ति भार, गिरवी या कोई अन्य ऋणभार या भौतिक अधिपत्य के साथ किसी ऋणभार की सहायता करना या उसे त्यागना या अन्य कोई व्ययन या संव्यवहार सम्मिलित है;

(36) "प्रणाली का उपयोग" से बिजली के पारेषण अथवा चक्रण हेतु प्रयुक्त वितरण प्रणाली का उपयोग अभिप्रेत है;

(37) "उपयोक्ता" से अभिप्राय वितरण प्रणाली का उपयोग करने वाले से है;

(38) अन्य सभी शब्दों, पदों व अभिव्यक्तियों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई हैं, और इन में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनके लिए अधिनियम में नियत किया गया है।

3. अवधि.— वितरण अनुज्ञप्ति आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूरी के आदेश में उल्लिखित तारीख से प्रवृत्त होगी तथा अनुज्ञप्ति में मंजूर निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए आदेश में उल्लिखित कालावधि तक लागू रहेगी :

परन्तु समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों की दशा में ये शर्तें 10 जून, 2004 से प्रवृत्त होंगी।

4. विधि, नियमों व विनियमों का पालन.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम, नियमों, आयोग द्वारा, समय-समय पर, जारी किये गये विनियमों, आदेशों व निदेशों और अन्य सभी प्रवृत्त विधियों के प्रावधानों का पालन करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, केवल जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति मंजूर होने के समय अथवा आयोग द्वारा विशेष तौर से इनमें बदलाव हेतु दी गई मंजूरी से इन शर्तों के प्रावधानों के पालन में छूट मिली हो के अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगा।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र, प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र तथा अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु जारी आदेशों व निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करेगा।

5. वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कृत्य.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण क्षेत्र में एक दक्ष, समन्वित व मितव्ययी वितरण प्रणाली को विकसित व सम्पोषित करेगा तथा उस वितरण क्षेत्र में अधिनियम, नियमों, आयोग के विनियमों तथा आयोग द्वारा दिए गए आदेशों व निदेशों के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को निम्न का अधिकार होगा कि—

(क) वह उत्पादन कम्पनियों, विद्युत व्यापारियों व अन्य व्यक्तियों से जिनके साथ वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत क्रय अथवा उपापन करने का करार अथवा व्यवस्था की हुई है ऐसे करार तथा व्यवस्था, जो आयोग द्वारा स्वीकृत अथवा

अनुमोदित है, के निबन्धनों व शर्तों अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टैरिफ के निबन्धनों व शर्तों के अनुसार, विद्युत क्रय, आयात या अन्यथा अर्जित कर सके;

- (ख) वह ऐसे व्यक्ति से जिसकी अनुज्ञप्ति प्रदत्त होने की तारीख को यथा विद्यमान उत्पादन इकाई वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से सीधे तौर पर जुड़ी है अथवा अंतरापृष्ठ है, विद्युत क्रय अथवा अर्जित कर सके ; परन्तु वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी भी विद्युत क्रय अथवा अर्जन के लिए की गई व्यवस्था से आयोग को अवगत करेगा और आयोग की साधारण अथवा विशेष मन्जूरी लेगा;
- (ग) वह किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा अनुज्ञप्तिधारी से आयोग द्वारा मन्जूर टैरिफ तथा निबन्धनों और शर्तों पर विद्युत क्रय या अन्यथा अर्जित कर सके;
- (घ) वह वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण क्षेत्र के भीतर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विद्युत के वितरण और/अथवा प्रदाय हेतु विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति की, जिसके लिए विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को अलग से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, नियुक्ति कर सके; परन्तु अपने प्रदाय क्षेत्र में विद्युत वितरण का उत्तरदायित्व अनुज्ञप्तिधारी का ही होगा;
- (ङ) वह विद्युत व्यापार के लिए अलग अनुज्ञप्ति की अपेक्षा के बिना विद्युत का व्यापार कर सके;
- (च) वह आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार विद्युत चक्रण के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी वितरण प्रणाली तक पहुँच दे सके;
- (छ) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय क्षेत्र में विद्युत प्रदाय की अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए विद्युत अथवा क्षमता अपेक्षित नहीं है, तो वह उस कालावधि में उस सीमा तक अनुबन्धित विद्युत अथवा क्षमता का विक्रय कर सके ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी केवल अनुज्ञप्ति के अनुसार, आयोग द्वारा मन्जूर टैरिफ तथा निबन्धनों व शर्तों पर किसी भी व्यक्ति को विद्युत विक्रय प्रदाय या उसका अन्यत्र व्ययन कर सकेगा ।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण अनुज्ञप्ति के अधीन अपनी अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए मितव्ययी रीति में और पारदर्शी उपापन ऊर्जा क्रय या उपापन प्रक्रिया के अधीन और समय-समय पर आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों, दिशा निर्देशों के अनुसार वांछित ऊर्जा का क्रय करेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी केवल आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 51 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुरूप ही किसी अन्य कारोबार में संलग्न होगा ।

(6) ऐसे प्रकरण को छोड़कर जबकि अनुज्ञप्त कारोबार के प्रयोजन के लिए ऋण दिया या जारी किया गया हो वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को ऋण देने या किसी बाध्यता के लिए कोई प्रतिभूति जारी करने से पूर्व आयोग की मन्जूरी प्राप्त करेगा । कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसरण में ऋण और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में व्यापार अग्रिम प्राप्ति हेतु को ऐसी मन्जूरी प्राप्त करने की अपेक्षा से अपवर्णित किया जाता है ।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अपने अनुज्ञप्त कारोबार के सम्बन्ध में, माल तथा सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए निम्न शर्तों के अध्याधीन, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की किसी भी नियंत्री या समनुषंगी कम्पनी या ऐसी नियंत्री कम्पनी की समनुषंगी कम्पनी को अनुबन्धित कर सकता है,—

(क) यह कि संव्यवहार अतिपरिचित आधार पर होगा और ऐसे मूल्य पर होगा जो कि परिस्थितियों के अनुरूप उचित और युक्तियुक्त हों ;

(ख) यह कि अनुज्ञप्त कारोबार के सम्बन्ध में माल तथा सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए संव्यवहार आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों के संगत हों ; और

(ग) यह कि अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित व्यवस्था के प्रारम्भ होने से पूर्व, आयोग को 15 दिन का नोटिस देगा और नोटिस के साथ समस्त सुसंगत विवरण उपलब्ध करेगा ।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी समनुषंगी या सह-कम्पनियाँ स्थापित कर सकेगा या विशेषाधिकारी की नियुक्ति कर सकेगा या प्रबन्ध संविधा कर सकेगा, जिसमें ऐसे कृत्यों को, जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के अधीन संचालित करने या चलाने के लिए प्राधिकृत है, संचालित करने के लिए बिलिंग अभिकर्ता की नियुक्ति भी सम्मिलित है :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी समनुषंगी या सह-कम्पनियों या विशेषाधिकारियों या अभिकर्ताओं या ठेकेदारों के समस्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा ।

(9) केवल उपरोक्त धारा (8) के सिवाय, आयोग की पूर्व मन्जूरी के बिना, वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के अधीन किसी भी कार्य को किसी भी व्यक्ति को अन्तारित या सौंप नहीं सकेगा ।

(10) वितरण प्रणाली में प्रचालन बाध्यताओं की अनुपस्थिति में आयोग के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित या प्रभारित किये जाने के लिए निर्दिष्ट लागू सभी टैरिफ व प्रभारों के भुगतान के बाद वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्तिधारियों, आबद्ध उत्पादन संयंत्र सहित उत्पादन कम्पनी तथा उपभोक्ता के प्रयोग हेतु वितरण प्रणाली में खुली पहुंच उपलब्ध करेगा ।

(11) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की पूर्व मन्जूरी के बिना—

(क) किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के क्रय या उसका प्रबन्ध ग्रहण करने या उसे अन्यथा अर्जित करने के लिए कोई संव्यवहार नहीं करेगा ;

(ख) किसी उत्पादन कम्पनी अथवा उत्पादन केन्द्र में फायदाप्रद हित अर्जित नहीं करेगा ; या

(ग) अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत न आने वाले किसी व्यक्ति को राज्य में विद्युत का पारेषण, वितरण या प्रदाय नहीं करेगा ।

(12) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को अपनी वितरण प्रणाली में उपलब्ध अधिशेष क्षमता तक मध्यवर्ती वितरण सुविधाएँ उपलब्ध करवाएगा तथा यदि अधिशेष क्षमता की उपलब्धता के बारे कोई विवाद उठता है, तो उसका निर्णय आयोग करेगा । मध्यवर्ती सुविधाओं के प्रयोग हेतु देय प्रभार, शर्तें और निबन्धन, आयोग द्वारा इस निमित्त जारी आदेश के अध्वधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आपसी सहमति से तय किए जाएँगे । किसी असहमति की स्थिति में उसका विनिश्चय आयोग करेगा ।

6. लेखे.— (1) अधिकतम पूंजी संघटन अवधारित करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने कुल वित्तीय नियोजन, बजट तथा संरचना (जिस में वे प्रमुख वित्तीय प्राचल (पैरामीटर) जो

वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने निष्पादन का अनुश्रवण (मनीटर) करने के लिए अपनाएगा, भी हैं) का अध्ययन करवाएगा ।

(2) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त कारोबार सम्बन्धित इन विनियमों में सामान्य शर्तों व मामलों के प्रयोजन हेतु प्रथम अप्रैल से वित्तीय वर्ष आरम्भ हो कर आगामी 31 मार्च तक चलेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त कारोबार और किसी अन्य कारोबार के सम्बन्ध में,—

(क) ऐसे लेखा अभिलेख रखेगा जो प्रत्येक ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में अपेक्षित होगा जिस से कि अनुज्ञप्त कारोबार को युक्तियुक्त रूप में लगाने योग्य राजस्व, लागत, अस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों और निवेश, को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तकों में उन अन्य कारोबार से, जिनमें वितरण अनुज्ञप्तिधारी लगा हुआ है, पृथक्कृत: अभिज्ञेय है ;

(ख) ऐसे लेखा अभिलेखों से प्रचलित आधार पर निम्न लेखा विवरण तैयार कर आयोग को भेजेगा—

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छः मास के सम्बन्ध में ऐसे आधारीय दस्तावेजों और जानकारी सहित, यथा आयोग समय-समय पर निर्दिष्ट करे, अर्ध-वार्षिक लाभ-हानि लेखा, नकद प्रवाह कथन और तुलन-पत्र ;

(ii) तैयार लेखा विवरण के सम्बन्ध में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये यह अधिकथित करते हुए किसी संपरीक्षक की रिपोर्ट में यह बताया गया हो कि क्या उनकी राय में इन विवरणों को उचित रूप में तैयार किया गया है और ये राजस्व, लागत, अस्तियों, दायित्वों, आरक्षितियों और निवेशों का, अथवा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में माना जा सकने वाले का, जिनसे विवरण सम्बन्धित है, सत्य और ऋजु दृष्टिकोण देते हैं ;

(iii) प्रत्येक आधे वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे की एक प्रति देगा, जो उस अवधि में जिस से वह सम्बन्धित है के तीन माह के पश्चात् के न हो, और लेखा विवरण तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट देगा जो उस वित्तीय वर्ष, जिस से वह

सम्बन्धित है, की समाप्ति के पश्चात् की न हो ।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना, पूर्व वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लागू वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लेखा विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में भार या अनुपात या राजस्व का आवंटन या व्ययों के आधार को सामान्यतः परिवर्तित नहीं करेगा । भार या राजस्व के अनुपात या व्यय में, यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो, तो वह कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के लेखा मानको या विनियमों और इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही होगा ।

(5) यहां किसी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लेखा विवरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत भार या अनुपात या आवंटन के आधार को परिवर्तित कर दिया है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि आयोग द्वारा अनुरोध किए जाने पर उस आधार पर, जो अव्यवहित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में लागू होता था, लेखा विवरण तैयार करेगा ।

(6) उप-विनियम (3) के अधीन वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित या निर्देशित न कर दिया जाए,—

- (क) यहां दिए गए तरीके से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखे तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे;
- (ख) अंगीकृत की गई लेखा-नितियों को अधिकथित करेंगे;
- (ग) सामान्यतः स्वीकार किए गए भारतीय लेखा मानको के अनुरूप तैयार किए जाएंगे ;
- (घ) आयोग द्वारा समय-समय पर नियत किए गए स्वरूप के अनुसार तैयार किये जाएंगे ।

(7) अनुज्ञप्त कारोबार या अन्य कारोबार में युक्तियुक्त रूप में लगने योग्य व्ययों के दायित्वों हेतु संदर्भित ऐसी पूंजीगत आस्तियाँ, जो कि सिद्धांतिक रूप से ऐसे कारोबार और उस पर व्याज से सम्बन्धित हैं, एवं कराधान को छोड़कर, मानी जाएंगी ।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (3) के अधीन तैयार

किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित लेखा विवरण और प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में संपरीक्षक रिपोर्ट, आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से, प्रकाशित की जाएगी तथा उसकी प्रति द्विप्रतिलिपिकरण के युक्तियुक्त मूल्य से अनाधिक की कीमत पर किसी भी व्यक्ति के अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध करवाई जाए ।

7. अनुचित अधिमानता का प्रतिषेध.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्युत वितरण क्षेत्र व प्रदाय क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति को अनुचित अधिमानता नहीं देगा:

परन्तु यह कि यदि अधिनियम की धारा 65 के अधीन साहायिकी के भुगतान हेतु आयोग या राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा उपभोक्ताओं में भेद किया जाता है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी कोई अनुचित अधिमानता देना नहीं माना जाएगा ।

8. आयोग को जानकारी देने के उपबन्ध.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अविलम्ब ऐसी जानकारी, अभिलेख अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी के या जो किसी अन्य कारोबार से सम्बन्धित विवरण जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर उसके स्वयं के प्रयोजन के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य पारेषण उपयोगिता और राज्य भार प्रेषण केन्द्र के प्रयोजन के लिए अपेक्षित समझा जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 128 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट सूचना रखेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यथासम्भव शीघ्र आयोग को वितरण प्रणाली के किसी भाग को प्रभावित करने वाली किसी घटित प्रमुख घटना को और ऐसी घटना होने की तारीख से दो मास के भीतर, आयोग को अधिसूचित करेगा —

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की जानकारी में घटना तथा उसके कारणों के सम्बन्ध में तथ्यों का पूर्ण विवरण देते हुए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;

(ख) यदि खण्ड (क) के अधीन रिपोर्ट देने में ऐसी घटना की तारीख से दो माह से अधिक समय लगना सम्भाव्य हो, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी घटना घटने की तारीख से एक मास के भीतर ऐसे सभी विवरणों, जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी उचित प्रकार से प्रस्तुत कर सके, सहित एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और

उन कारणों, जिनकी वजह से घटना की पूर्ण रिपोर्ट देने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दो माह से अधिक समय अपेक्षित है, को अधिकथित करेगा ;

(ग) प्रमुख घटना से संबंधित सभी पक्षकारों और अन्य ऐसे व्यक्तियों, जिन के लिए आयोग द्वारा निदेशित किया जाए, को रिपोर्ट की प्रतियाँ देगा ।

(4) आयोग, स्वविवेकानुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर किसी स्वतन्त्र व्यक्ति द्वारा तैयार की गई किसी प्रमुख घटना पर रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा कर सकेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे बिन्दुओं का अध्ययन करेगा जिस से वितरण प्रणाली और वितरण कारोबार से जुड़े अन्य बिन्दुओं जिन्हें आयोग ऐसी घटना को घटित होने से टालने हेतु आवश्यक समझता हो, में सुधार हो ।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को किसी भी घटना जो उसे मन्जूर अनुज्ञप्ति के अधीन बाध्यताएँ, जिसमें दूसरों के कार्य या लोप से होने वाले कृत्य भी सम्मिलित हैं, निभाने में बाधक हो, तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में सम्यक् रूप में सूचित करेगा ।

(7) आयोग, किसी भी समय उप-विनियम (3) से (6) के उपबन्धों का उन घटनाओं जिन्हें आयोग विशिष्टतः निदेशित करे पालन करने की वितरण अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षा कर सकेगा और वितरण अनुज्ञप्तिधारी उनका अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा, भले ही ऐसी घटनाएँ प्रमुख घटनाएँ भी हों; परन्तु उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिस तारीख को आयोग ऐसी अपेक्षा को अनुज्ञप्तिधारी को अधिसूचित करता है ।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्ति के लागू होने के तीन माह के भीतर आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि हेतु कारोबार योजना प्रस्तुत करेगा और उसका वार्षिक रूप से अद्यतन करेगा । कारोबार योजना में वर्ष-वार भार-वृद्धि, विनिर्दिष्ट कार्रवाई योजना सहित वर्ष-वार वितरण में होने वाली हानि में कमी का प्रस्ताव, अन्तर-फेस बिन्दुओं को मापने के लिए मीटरिंग योजना, विनियम 9 के अनुसार विनिधान योजना, पूर्व हानियों का उपचार ऋण, पुर्नसंरचना योजना, लागत कटौती योजना, संभावित लाभ-हानि लेखे, संभावित तुलन-पत्र, संभावित रोकड़ उपलब्धता विवरण और संभावित महत्वपूर्ण वित्तीय प्राचल (पैरामीटर्स) सम्मिलित होंगे ।

(9) आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही पर यह

अपेक्षा करेगा कि वह पूर्व वित्तीय वर्ष की योजना के क्रियान्वयन की तुलना में, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित योजना, को सूचित करे ।

9. विनिधान.— (1) वितरण कारोबार में होने वाले विनिधान हेतु आयोग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों, दिशा-निर्देशों और आदेशों का वितरण अनुज्ञप्तिधारी सम्यक् रूप में पालन करेगा ।

(2) राज्य में दक्ष, समन्वित व मितव्ययी वितरण प्रणाली को बनाने, रख-रखाव व चलाने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी कर्तव्यबोध के अनुसार प्रबुद्ध विनिधान करेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी विनियम 8 के उप-विनियम (8) के अन्तर्गत संबन्धित अवधि के लिए विनिधान योजना के विवरण सहित कारोबार योजना को विनिधान योजना के रूप में आयोग के समक्ष मन्जूरी हेतु प्रस्तुत करेगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग का समाधान करते हुए यह प्रदर्शित करेगा कि —

(क) वितरण प्रणाली में विनिधान योजना में दी गई विनिधान की आवश्यकता है ;

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने ऐसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए नई वितरण प्रणाली आस्तियों का विनिधान करने के लिए या अर्जित करने के लिए प्रस्तावों के समस्त लाभप्रद विकल्पों के आर्थिक, तकनीकी प्रणाली और पर्यावरणीय पहलुओं का परीक्षण कर लिया है ।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के अन्त तक निम्न सूचना देगा —

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियान्वयन में ली जाने वाली विनिधान स्कीम के ब्यौरे सहित वार्षिक विनिधान योजना ; और

(ख) पूर्व वर्ष के लिए आयोग द्वारा मन्जूर विनिधान योजना के सम्बन्ध में वास्तविक कार्यान्वयन की तुलना के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विनिधान स्कीम के क्रियान्वयन में की गई प्रगति ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा उप-विनियम (3) के अधीन मन्जूर विनिधान

योजना में समाविष्ट न की गई मुख्य विनिधान योजनाओं को, आयोग की पूर्व मन्जूरी के बिना, हाथ में नहीं लेगा और ऐसी मन्जूरी लेने हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग का समाधान करते हुए उप-विनियम (3) में वर्णित तत्वों को प्रदर्शित करेगा ।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा यथा-निर्दिष्ट पारदर्शी निविदा प्रक्रिया अपना कर उपस्कर, सामग्री और/या मुख्य विनिधान से सम्बन्धित सेवाओं के उपापन हेतु निविदाएँ आमन्त्रित कर उन्हें अन्तिम रूप देगा । वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग के परामर्श से :-

- (i) सुनिश्चित करेगा कि महत्वपूर्ण प्रबन्धकीय नीति तथा प्रक्रिया, जिस में विभिन्न कार्यवाहियों, मन्जूरियों, क्रय आदेश देने, सुपर्दगी सारणी तथा भुगतान इत्यादि की कार्यसूची भी सम्मिलित है, इस प्रकार से सुप्रवाहित है कि मन्जूर मानकों तथा संदर्भिकाओं के निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुपालन को सुकर बनाने हेतु उचित समय पर उचित कोटि का आवश्यक विनिधान हो सके;
- (ii) संदर्भिक मूल्य निर्धारण करेगा तथा वित्तीय नियन्त्रण रखने हेतु विकेंद्रित क्रय के लिए दर संविदा निर्णयित करेगा तथा ऐसे विकेंद्रित क्रय के बारे में अधिकतम वित्तीय अनुपात प्राप्त करने के लिए तालिका नियन्त्रण करेगा ।

(7) इस विनियम के प्रयोजन हेतु "मुख्य विनिधान" से वितरण सुविधाओं के अर्जन हेतु या उसमें नियोजित विनिधान अभिप्रेत है, जिसकी लागत जब समस्त कार्यसम्पादन में अन्य सभी विनिधानों या अर्जनों (यदि कोई हो), के रूप में संकलित की जाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर विशेष शर्तों में यथा अन्तर्विष्ट लागू या आयोग द्वारा समय-समय पर अन्यथा साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित राशि के बराबर या उससे अधिक हो ।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उप-विनियम (3) और (5) में आने वाले वितरण कारोबार के अतिरिक्त अन्य कारोबार में निवेश करने का अधिकार होगा, परन्तु टैरिफ के अवधारण हेतु ऐसे विनिधान पर विचार करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग का समाधान करेगा कि ऐसे वितरण कारोबार के लिए विनिधान आवश्यक था और यह विनिधान दक्षपूर्ण, समन्वित और मितव्ययी ढंग से किया गया है ।

(9) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग को "प्रत्याशित (सम्भावित) राजस्व गणना" के साथ आयोग द्वारा मन्जूर परियोजनाओं को समाविष्ट करते हुए वार्षिक विनिधान योजना के मुख्य बिन्दु एवं आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आयोजित अन्य सभी

परियोजनाओं को, जिसमें आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है आयोग को, मन्जूरी हेतु प्रस्तुत करेगा और उक्त वित्तीय वर्ष में उक्त विनिधान योजना के अनुसार निवेश करेगा :

परन्तु यदि किसी अनपेक्षित आकस्मिताओं के कारण वार्षिक विनिधान योजनाओं में सूचीबद्ध परियोजना के भीतर निधियों का पुनराबंटन की आवश्यकता हो, तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसा पुनराबंटन इस प्रकार कर सकता है जब तक कि वैयक्तिक परियोजना के सम्बन्ध में वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू विशिष्ट शर्तों में या अन्यथा आयोग के साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्धारित राशि से अधिक न हो। वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे पुनराबंटन को आयोग को निवेश करने के 7 दिनों के भीतर, सम्यक् रूप से सूचित करेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण वितरण अनुज्ञप्तिधारी को परियोजना में ऐसा निवेश, जो वार्षिक विनिधान योजना में सम्मिलित नहीं है, करना अपेक्षित है, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि यह मुख्य विनिधान नहीं है और उप-विनियम (8) में दी गई की शर्तों के अनुरूप है, ऐसा कर सकता है ।

10. परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपयोजित तथा अनुपयोजित परिसम्पत्तियों, अनुत्पादक तथा अलाभकर परिसम्पत्तियों को पृथक्कृत करेगा और अनुत्पादक तथा अलाभकर परिसम्पत्तियों की परिसम्पत्ति-सूची तैयार करेगा ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी "स्थिर परिसम्पत्ति-रजिस्टर" तैयार करेगा और चालू पूंजीगत संकर्म खाते में प्रतिबिम्बित राशि के समय-समय पर अन्वेषण यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि पूरे किए गए संकर्म, यथाशीघ्र पूर्ण होने पर "स्थिर परिसम्पत्ति-रजिस्टर" में अंतरित कर दिये गए हैं ।

(3) आयोग या तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी से स्वतन्त्र अभिकरण से परिसम्पत्तियों की आस्तित्व जाँच करवाने की उपेक्षा कर सकेगा या स्वयं उक्त जाँच अनुज्ञप्तिधारी के खर्च पर करेगा ।

(4) इस विनियम में उपबंधित के सिवाए, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, एकल संव्यवहार या संबन्धित संव्यवहार के समूह में किसी ऐसी आस्ति, जिसका प्रस्तावित अंतरण के समय वही मूल्य जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू आयोग द्वारा विशेष शर्तों के अधीन या अन्यथा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित राशि से अधिक हो, के प्रचालन नियंत्रण का अंतरण या त्यजन नहीं करेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा उप-विनियम (4) के अधीन तय मूल्य से अधिक के मूल्य की आस्ति के प्रचालन नियंत्रण का आयोग को पूर्व लिखित सूचना दिये बिना अंतरण या त्यजन नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी समस्त संबंधित तथ्यों को लिखित नोटिस के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रकट करेगा। आयोग नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर संव्यवहार के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकता है, और सामान्यतः वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर, और जहाँ आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त अतिरिक्त जानकारी माँगी जाती है, वहाँ आवेदन दायर करने के 60 दिनों के भीतर ऐसी शर्तों या उपांतरणों के अध्यधीन अंतरण व्यवस्था जैसी समुचित समझी जाए, को मन्जूर कर सकता है या आयोग अपने लिखित आदेश द्वारा कारणों को बताते हुए इसे न मन्जूर कर सकता है।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उप-विनियम (5) के अधीन दिए गए किसी नोटिस में वर्णित किसी के प्रचालन नियंत्रण का अंतरण या त्यजन कर सकेगा जहाँ कि :-

(क) आयोग लिखित में यह पुष्टि करता है कि वह प्रचालन नियन्त्रण का अंतरण या त्यजन ऐसी शर्तों के अध्यधीन है जैसी कि आयोग द्वारा अधिरोपित की जाएँ ; या

(ख) आयोग उप-विनियम (5) के अधीन दिये गए नोटिस की अवधि के भीतर प्रचालन नियंत्रण के ऐसे अंतरण या त्यजन पर कोई आपत्ति को लिखित में वितरण अनुज्ञप्तिधारी को सूचित नहीं करता है और अंतरण पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया से प्रभावी होता है।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी आस्ति पर प्रचालन नियंत्रण का अंतरण या त्यजन भी कर सकेगा, जहाँ कि -

(क) आयोग ने निम्न के सम्बन्ध में सामान्य सहमति (चाहे शर्तों के अध्यधीन हो या न हो) अंतर्विष्ट करते हुए इस विनियम के प्रयोजन हेतु निर्देश जारी कर दिये हों,-

(1) विनिर्दिष्ट विवरण का संव्यवहार, और/या

(2) विनिर्दिष्ट विवरण की आस्ति के प्रचालन नियंत्रण का अन्तरण या त्यजन और/या

- (3) प्रचालन नियन्त्रण के अन्तरण या त्यजन शर्तों के अनुसार है जिसके अधीन सहमति है, या

(ख) प्रचालन नियन्त्रण का अन्तरण या त्यजन किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित है ; या

(ग) प्रश्नगत आस्ति किसी अन्य कारोबार के सम्बन्ध में जो अन्नयतः या प्राथमिक रूप से वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अर्जित और उपयोग में लाई गई थी और इस से भूमि में कोई विधिक या हितकारी हित नहीं होता है या वितरण प्रणाली का कोई भाग नहीं है या अन्यथा अनुज्ञप्त कारोबार के लिए अपेक्षित आस्ति नहीं है।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उसकी विनिधान आवश्यकताओं के वित्तपोषण को सुकर बनाने के साधन के रूप में आस्तियों का उपयोग निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए करने का हकदार होगा, जिसमें ऋण वित्तपोषण और प्राप्यों का प्रतिरक्षण सम्मिलित है :-

(क) यह कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत करार के प्रारम्भ की तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व ऐसे अनुबन्ध के बारे में आयोग को सूचित करेगा;

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आस्तियों के ऐसे उपयोग में, विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रीति से कार्य करता है ; और

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली में आस्तियों पर प्रचालन नियन्त्रण प्रतिधारित करता है ।

(9) इस विनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी आपातकालीन अवस्था में, वितरण अनुज्ञप्तिधारी किसी भी आस्ति का इस शर्त पर अन्तरण कर सकता है कि ऐसे किसी संव्यवहार के अव्यविहत पश्चात् वितरण अनुज्ञप्तिधारी संव्यवहार की आपातकालीन प्रतिस्थितियों के विस्तृत तथ्यों और किए गए संव्यवहार का ब्यौरा दें कर आयोग की कार्योत्तर अनुमति प्राप्त करेगा। यह वितरण अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व होगा कि वह आस्ति के अन्तरण के लिए उत्पन्न आपातकालीन आवश्यकता को आयोग की तुष्टी के अनुसार सिद्ध करे ।

11. अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान.— (1) ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जैसे कि आयोग निर्दिष्ट करे, अनुज्ञप्तिधारी आयोग को हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

(कारवार संचालन) विनियम, 2005 या विशेष शर्तों में उल्लिखित प्रारम्भिक और सामायिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान करेगा ।

(2) जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी शोध्य तिथि तक उप-विनियम (1) के अधीन किसी भी देय शुल्क का भुगतान आयोग को करने में असफल रहता है, वहाँ —

(क) अन्य दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वितरण अनुज्ञप्तिधारी शेष देय राशि पर 1.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज बकाया रकम पर देने का दायी होगा । ब्याज उस दिन के पश्चात् की अवधि पर देय होगा जिसको कि रकम शोध्य होती है और उस दिन को समाप्त होगा जिस तारीख को आयोग को भुगतान किया जाता है ; तथा

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगातार बकाया होने की स्थिति में आयोग वितरण अनुज्ञप्ति को निलम्बित या प्रतिसंहरित कर सकता है ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ के लिए संकलित राजस्व के अवधारण में व्यय के रूप में इस विनियम के अधीन उसके द्वारा संदत्त किए गए किसी भी शुल्क को हिसाब में लेने का हकदार होगा :

परन्तु इस में देरी से किए गए भुगतान पर संदत्त ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

12. वितरण अनुज्ञप्ति का निलम्बन.— (1) धारा 24 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अध्याधीन रहते हुए, जहां ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जो आयोग के लिए लोकहित में ऐसा करने के लिए आवश्यक बनाती हैं, तो आयोग एक वर्ष की अवधि से अनाधिक अवधि के लिए, वितरण अनुज्ञप्ति को निलम्बित कर सकता है यदि आयोग के विचार से वितरण अनुज्ञप्तिधारी—

(क) उपभोक्ताओं को विद्युत की गुणवत्ता (क्वालिटी) के सम्बन्ध में मानकों के अनुरूप विद्युत के अवाधित प्रदाय को बनाए रखने में लगातार असफल रहता है; या

(ख) अधिनियम के उपबन्धों द्वारा उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ रहता है ;

(ग). आयोग द्वारा अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निर्देश का अनुपालन करने में बराबर व्यतिक्रम करता है; या

(घ) अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों को भंग करता है ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने से पूर्व, आयोग अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम (एक माह) की लिखित सूचना (नोटिस) उन आधारों को सूचित करते हुए देगा जिन पर अनुज्ञप्ति को निलम्बित करने का प्रस्ताव है और प्रस्तावित निलम्बन के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उस सूचना (नोटिस) की अवधि के भीतर दर्शाए गए किसी कारण पर विचार करेगा ।

(3) इस विनियम के अधीन अनुज्ञप्ति को निलम्बित करते समय आयोग वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों के निर्वहन हेतु अनुज्ञप्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार एक प्रशासक की नियुक्ति करेगा और ऐसी नियुक्ति होने पर वितरण अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिताएं एक वर्ष से अनाधिक अवधि या उस तारीख तक के लिए जिसको ऐसी उपयोगिता का धारा 20 में अर्न्तविष्ट उपबन्धों के अनुसार विक्रय किया जाता है या अनुज्ञप्ति धारा 19 के अधीन प्रतिसंहरित की जाती है, जो भी बाद में हो, प्रशासक में निहित हो जाएंगी ।

13. प्रतिसंहरण की शर्तें.— (1) अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों और उसके अधीन बने विनियमों के अधीन, आयोग किसी भी समय, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाई प्रारम्भ कर सकेगा और यदि ऐसी कार्यवाइयों में प्रतिसंहरण के आधारों और लोकहित से उसका समाधान हो जाता है, वितरण अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण कर सकेगा, तो वह निम्नलिखित दशा में, अर्थात् :-

(क) जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग की राय में अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में अपेक्षित कोई भी बात को करने में जानबूझकर और विलम्बित व्यतिक्रम करता है ;

(ख) जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन करता है जिसके उल्लंघन से अनुज्ञप्ति अभिव्यक्त प्रतिसंहत हो जाए ;

(ग) जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति में नियत अवधि के भीतर या ऐसी

दीर्घ अवधि जिसे आयोग ने प्रदान किया हो, के भीतर —

- (i) आयोग को यह दर्शाने में असफल रहता है कि अनुज्ञप्ति में उसके ऊपर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का पूर्ण और दक्षतापूर्ण निर्वहन करने की स्थिति में है ; या
- (ii) अनुज्ञप्ति में अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप करने या फीस या अन्य प्रभार का संदाय करने में असफल रहता है;

(घ) जहाँ आयोग की राय में वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह उस पर अधिरोपित कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन पूर्णतः और दक्षता से निभाने में असमर्थ रहता है ; और

(ङ) जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग के सभी विनियमों, कोडों, और मानकों और आदेशों व निर्देशों के पालन में असफल रहता है या अन्यथा ऐसा कृत्य करता है, जिससे अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य आधारों पर वितरण अनुज्ञप्ति प्रतिसंहरणीय हो जाए ।

(2) जहाँ उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो आयोग आवेदन प्राप्त होने पर या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुज्ञप्ति को पूर्ण रूप से या उसके वितरण क्षेत्र के किसी भाग के लिए ऐसी शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझता हो, प्रतिसंहत कर सकेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने से पूर्व, आयोग, यदि उसकी राय में आवश्यक हो, मामला राज्य सरकार को भेज सकता है और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए वैकल्पिक प्रबन्ध करने के लिए सहमत होगा ।

14. अनुज्ञप्ति की शर्तों का संशोधन.— (1) आयोग, यदि लोकहित में आवश्यक समझता हो, अधिनियम की धारा 18 के अधीन अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों में परिवर्तन और संशोधन निम्न शर्तों पर कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) जहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव करते हुए आवेदन किया हो, वहाँ वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे आवेदन की सूचना को आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति से और विशिष्टियों सहित प्रकाशित करेगा ;

- (ख) किसी छावनी, हवाई अड्डा, दुर्ग, आयुधशाला या कैम्प के या रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार के अधिभोग में/के किसी भवन या स्थान के सभी या किसी भाग को समाविष्ट करने वाले प्रदाय क्षेत्र में परिवर्तन या उपांतरण का प्रस्ताव करने वाले आवेदन की दशा में, कोई भी परिवर्तन या उपांतरण केवल केन्द्रीय सरकार की सहमति के बिना न किया जाएगा ;
- (ग) जहाँ किसी अनुज्ञप्ति में किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन से अन्यथा कोई परिवर्तन या संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया हो, आयोग ऐसे प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन को ऐसी विशिष्टियों सहित और ऐसी रीति से प्रकाशित करवाएगा, जैसे आयोग उचित समझे ;
- (घ) आयोग कोई भी परिवर्तन या संशोधन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसने सूचना के प्रथम प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर प्राप्त सभी सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं कर लिया हो ।

15. विवाद समाधान.— (1) आयोग को अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1)

के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 158 और आयोग के विनियमों के अनुसरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी या किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कम्पनी के बीच विवाद को न्यायनिर्णित करने या हल करने के लिए मध्यस्थता करने अथवा किसी व्यक्ति को माध्यस्थता के रूप में मनोनीत करने का अधिकार होगा ।

(2) आयोग, यथास्थिति, स्वयं उप-विनियम (1) के अधीन विवादों की माध्यस्थता कार्यवाई को प्रारम्भ और संचालित कर सकता है या विवादों को आयोग के कारोबार संचालन विनियमों के अनुसार अन्य की मध्यस्थता के लिए निवेदित कर सकता है ।

16. ग्रीड कोड का अनुपालन.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ग्रीड कोड के उन उपबन्धों का पालन करेगा जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली या अन्यथा उसके किसी क्रियाकलाप पर लागू हैं ।

(2) आयोग, किसी भी प्रभावित उत्पादन कम्पनी, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य पारेषण उपयोगिता, राज्य भार प्रेषण केन्द्र और विद्युत व्यापारियों, से परामर्श के उपरान्त, ग्रीड कोड के ऐसे भागों के सम्बन्ध में उप-विनियम (1) के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी को, उस हद तक जैसे आयोग आदेशित करे, उसके दायित्व से मुक्त करते हुए निदेश जारी कर सकता है ।

(3) अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा ग्रिड कोड विनिर्दिष्ट होने तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी अन्तरिम ग्रिड कोड का पालन करेगा।

17. विद्युत प्रदाय कोड और वितरण कोड.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा, समय-समय पर, यथानिर्देशित, विद्युत प्रदाय कोड तथा वितरण कोड का पालन करेगा।

(2) (क) विद्युत प्रदाय कोड में अन्य बातों के सिवाय, विद्युत प्रभारों की वसूली, विद्युत प्रभारों के भुगतान के अन्तराल, उसके असंदाय के लिए विद्युत प्रदाय की लाईन को काटने, प्रदाय की पुनः स्थापना, विद्युत लाईनों या मीटर को बिगाड़ने, नुकसान या क्षति पहुंचाने, वितरण अनुज्ञप्तिधारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी व्यक्ति को प्रदाय की लाईन काटने या मीटर काटने या मीटर बदलने के लिए प्रवेश करने, विद्युत लाईनों या विद्युत संयंत्र या मीटर के, परिवर्तन या उनके रख-रखाव करने के लिए उपबन्ध किये जाएंगे।

(ख) आयोग अनुज्ञप्तिधारी के कहने पर अनुज्ञप्तिधारी को, विद्युत प्रदाय कोड के अधीन अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के ऐसे भागों व ऐसी सीमा तक, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, उसके दायित्व से मुक्त करते हुए निर्देश जारी कर सकता है।

(3) विद्युत प्रदाय कोड के सिवाय, आयोग, समय-समय पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारी के वितरण क्षेत्र में लागू होने वाली विद्युत प्रदाय की अन्य शर्तें मंजूर कर सकता है।

(4) अन्य बातों के साथ-साथ वितरण कोड संयोजनों (कनैक्शनों) से सम्बन्धित सभी तात्त्विक तकनीकी पहलुओं, और वितरण प्रणाली से संयोजित विद्युत लाईनों और विद्युत संयंत्रों और उपकरणों के परिचालन सहित वितरण प्रणाली के परिचालन व उपयोग, जो जहाँ तक सुसंगत हों, वितरण प्रणाली के परिचालन व उपयोग के लिए उपबन्धित करेगा और इस में वितरण योजना व संयोजन (कनैक्शन) कोड, परन्तु इन तक सीमित नहीं होकर, निम्न को सम्मिलित करेगा, अर्थात्:—

(क) योजना कोड जिसमें प्रदाय क्षेत्र में वितरण लाईनों और सर्विस लाईनों को बिछाने तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसकी वितरण प्रणाली के विकास व योजना में उपयोजित की जाने वाली तकनीकी व डिजाईन मानदण्ड व प्रक्रिया विनिर्दिष्ट हो;

(ख) संयोजन (कनैक्शन) शर्तें, जिनमें अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजित या संयोजन (कनैक्शन) लेने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुपालन के लिए

तकनीकी रूपांकन और प्रचालन मानक विनिर्दिष्ट किए गए हों; और वितरण कोड जिसमें उन शर्तों का जिनके अधीन अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली का प्रचालन करेगा और जिनके अधीन कोई व्यक्ति अपने संयंत्र और/अथवा अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के सम्बन्ध में, जहाँ तक प्रदाय की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, सामान्य और असामान्य दोनों परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के सुरक्षित प्रचालन हेतु, वितरण प्रणाली का प्रचालन करेगा।

(5) वितरण कोड का इस तरह रूपांकन किया जाएगा कि एक दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी वितरण प्रणाली का विकास, रख-रखाव और प्रचालन हो सके।

(6) जब तक विद्युत प्रदाय कोड की शर्तें या वितरण कोड लागू नहीं हो जाता, तब तक वितरण अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसे आयोग निर्देशित या अनुज्ञात करे, उसी पद्धति को अपनाएगा जिसे राज्य में प्रदाय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनाया जाता रहा है।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, समय-समय पर, जैसे उचित हो, पारिषण अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारिक अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन कम्पनियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जैसे आयोग आदेशित करे, से परामर्श के पश्चात्, वितरण कोड व उसके कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन करेगा। जब आयोग ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट करे, अनुज्ञप्तिधारी भी ऐसे पुनर्विलोकन करेगा। ऐसा पुनर्विलोकन करते समय अनुज्ञप्तिधारी आयोग को निम्नलिखित भेजेगा :-

(क) पुनर्विलोकन के परिणाम पर एक रिपोर्ट;

(ख) वितरण कोड का प्रस्तावित पुनरीक्षण, जिसे अनुज्ञप्तिधारी (ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए) वितरण कोड और उसकी अनुज्ञप्ति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु युक्तियुक्त समझता हो;

(ग) ऐसे पुनर्विलोकन के दौरान प्राप्त समस्त लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियाँ :

(8) वितरण कोड, विद्युत प्रदाय कोड और प्रदाय शर्तों के समस्त पुनरीक्षणों का आयोग से अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(9) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा अनुरोध किये जाने पर सुसंगत समय पर प्रवृत्त वितरण कोड, विद्युत प्रदाय कोड और प्रदाय की शर्तों और उसकी प्रक्रिया

ऐसे मूल्यों पर उपलब्ध करवाएगा जो उसके द्विप्रतिलिपीकरण की युक्तियुक्त लागत से अधिक न हो।

(10) अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली और उसकी वितरण सुविधाओं के संनिर्माण से संबंधित विद्यमान कोड और पद्धतियों का संकलन अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के 90 दिनों के भीतर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान कोड और पद्धति, ऐसे उपांतरणों सहित जैसा कि आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए, का पालन करेगा। संनिर्माण पद्धतियों को सुसंगत तकनीकी विकास और परिवर्तन के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुनर्विलोकित कर उन्नयित किया जाएगा।

18. उपभोक्ता सेवा.—(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित का पालन करेगा अर्थात्:—

I. बिलों के भुगतान के लिए पद्धति कोड.—

(क) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के 90 दिनों के भीतर आयोग की मन्जूरी के लिए उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान से सम्बद्ध पद्धति कोड तैयार तथा प्रस्तुत करेगा। जिसमें उपभोक्ताओं को, जिन्हें बिलों के भुगतान में होने वाली कठिनाईयाँ आती हों, सहायता देने के लिए दिशा निर्देश और उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान न किए जाने की दशा में बिजली काटने की प्रक्रिया दी जाए। मन्जूरी देते समय आयोग पद्धति कोड में ऐसे उपांतरण कर सकता है जो आवश्यक समझे जाएँ ;

(ख) यह अवधारित करने के लिए कि इसमें या इसके कार्यान्वयन की रीति में कोई उपांतरण करना आवश्यक है, आयोग, अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, या अन्यथा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से पद्धति कोड तथा उस रीति, जिसमें इसे कार्यान्वित किया गया है, के पुनर्विलोकन की अपेक्षा कर सकता है ;

(ग) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों से परामर्श से, पद्धति कोड का पुनर्विलोकन करेगा तथा पद्धति कोड में संशोधन, जिसे अनुज्ञप्तिधारी चाहता हो, को, ऐसे अभ्यावेदन सहित जिसे अनुज्ञप्तिधारी ने प्राप्त किया हो परन्तु उसे वह स्वीकार नहीं करता है, आयोग की मन्जूरी के लिए प्रस्तुत कर सकता है। आयोग, यदि आवश्यक समझे, बिलों के भुगतान के लिए पद्धति कोड में

उपांतरण कर सकता है ;

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी -

- (1) आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति में उपभोक्ता का ध्यान पद्धति कोड और उसके प्रत्येक पुनरीक्षण की ओर आकृष्ट करेगा और यह भी बताएगा कि कोड की अन्तिम रूप की प्रति का निरीक्षण कैसे तथा उसकी प्रति कैसे प्राप्त होगी;
- (2) समय-समय पर पुनरीक्षित कोड की प्रति निरीक्षण हेतु सामान्य कार्य-समय में जनता को उपलब्ध करवाएगा;
- (3) किसी भी नए उपभोक्ता को, और किसी भी अन्य व्यक्ति को, अनुरोध किए जाने पर, पद्धति कोड की अद्यतन प्रति, ऐसे मूल्य पर, जो उसके द्विप्रतिलिपीरकण की युक्तियुक्त लागत से अधिक न हो, उपलब्ध करेगा;

(ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा यथानिर्देशित उपांतरणों सहित उपभोक्ता द्वारा विद्युत बिलों के भुगतान के लिए अपनाई गई प्रचलित पद्धति और प्रक्रिया का तब तक पालन करेगा जब तक इस अनुच्छेद में वर्णित उपभोक्ता द्वारा बिलों के भुगतान के लिए पद्धति कोड को आयोग की मंजूरी से अपनाया न जाए ।

II शिकायत निपटान प्रक्रिया :

- (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं की शिकायतों के दूर करने के लिए अधिनियम की धारा 42 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों व दिशा-निर्देशों के अनुसार एक फोरम की प्रस्थापना करेगा ।
- (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग जैसे निर्दिष्ट करे, अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने के उपरान्त और आयोग की मंजूरी से, युक्तियुक्त समय के भीतर, शिकायतों को दूर करने के लिए फोरम के साथ-साथ अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करेगा । आयोग धारा 87 के अधीन गठित राज्य सलाहकार समिति से या किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, जिन्हें आयोग सम्भावित प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं

के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला समझे, के साथ विचार विमर्श कर सकता है और उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने वाली प्रक्रिया को मंजूरी देने से पूर्व प्रक्रिया में ऐसे उपांतरण, जिसे यह आवश्यक समझता हो, कर सकता है ।

(ग) यह आधारित करने के लिए कि इस में या इसके कार्यान्वयन की रीति में कोई उपांतरण करना आवश्यक है, आयोग अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, या अन्यथा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से तैयार की गई शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया तथा उस रीति, जिससे कार्यान्वयन किया गया है, के पूर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकता है ।

(घ) इस प्रकार बनाई गई किसी प्रक्रिया में, जिसमें सभी पुनरीक्षण भी सम्मिलित हैं, विभिन्न प्रकार की शिकायतों की छानबीन व निपटारा करने के लिए समय-सीमा अधिसूचित की जाएगी ।

(ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी बनाई गई प्रक्रिया में प्रस्तावित पुनरीक्षण को आयोग की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा ।

(च) वितरण अनुज्ञप्तिधारी :-

(1) आयोग द्वारा निर्दिष्ट रीति में उपभोक्ता का ध्यान शिकायतों को दूर करने की प्रक्रिया एवं इसमें प्रत्येक पुनरीक्षण की ओर आकृष्ट करेगा तथा यह भी बताएगा कि उक्त प्रक्रिया के अन्तिम रूप की प्रति का निरीक्षण कैसे होगा या उसकी प्रति कैसे प्राप्त होगी;

(2) समय-समय पर शिकायतों को दूर करने की पुनरीक्षित प्रक्रिया की प्रति निरीक्षण हेतु अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्धित कार्यालयों में सामान्य कार्य - समय पर जनता को उपलब्ध करवाएगा ;

(3) प्रत्येक नए उपभोक्ता को, और किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरोध किए जाने पर, शिकायतों को दूर करने वाली प्रक्रिया की अद्यतन प्रति ऐसे मूल्य पर उपलब्ध करवायेगा जो उसकी द्विप्रतिलिपिकरण की युक्तियुक्त लागत से अधिक न हो ।

III' उपभोक्ता अधिकार विवरण:

(क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की मन्जूरी से, युक्तियुक्त अवधि में, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, उपयोगिता के विभिन्न क्रिया-कलापों, विवाद निपटारा क्रियाविधि, उपभोक्ता अधिकार तथा दायित्व इत्यादि से सम्बन्धित सहायक सामग्री, जो विभिन्न उपभोक्ता समूहों और आम जनता को उपयोगी हो, को तैयार, प्रकाशित और घोषित करके व्यापक लोक अन्वोन्य क्रिया योजना विकसित करके आयोग को प्रस्तुत करेगा तथा सलाहकार समितियों के माध्यम से कार्यान्वित करेगा।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग जैसे निर्दिष्ट करे, अनुज्ञप्ति के प्रभावी होने के उपरान्त और आयोग की मन्जूरी से युक्तियुक्त समय, या अन्य समय जिसे आयोग अनुज्ञात करे, के भीतर उपभोक्ता अधिकार विवरण, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को दी जाने वाली सेवाओं हेतु उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई हो, तैयार करेगा और आयोग की मन्जूरी के लिए भेजेगा। आयोग धारा 87 के अधीन गठित राज्य सलाहकार समिति से और अन्य व्यक्तियों के संगठनों, जिन्हें आयोग सम्भावितया प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला समझें, के साथ विचार-विमर्श कर सकता है और विवरण में ऐसे उपांतरण, जिन्हें वह लोकहित में आवश्यक समझता हो, कर सकता है।

(ग) यह अवधारित करने के लिए कि इसमें या इसके कार्यान्वयन की रीति में कोई उपांतरण करना आवश्यक है, आयोग अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, या अन्यथा, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से तैयार किए गए उपभोक्ता अधिकार विवरण और उस रीति जिसमें उसका कार्यान्वयन किया गया है के पुनर्विलोकन की अपेक्षा कर सकता है।

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता अधिकार विवरण में संशोधन, जिसे वह करना चाहता है को उस अभ्यावेदन सहित जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी स्वीकृत नहीं कर सकता है, आयोग की मन्जूरी के लिए प्रस्तुत कर सकता है। आयोग, यदि आवश्यक समझे, उपभोक्ता अधिकार विवरण में उपांतरण कर सकता है।

(ङ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी -

(1) आयोग निदेशित रीति में उपभोक्ताओं का ध्यान उपभोक्ता अधिकार विवरण और इसके प्रत्येक पुनरीक्षण की ओर आकृष्ट करेगा और यह भी बताएगा कि उपभोक्ता अधिकार विवरण के अन्तिम रूप की प्रति का निरीक्षण कैसे होगा तथा

उसकी प्रति कैसे प्राप्त होगी ;

- (2) समय-समय पर उपभोक्ता अधिकार विवरण की पुनरीक्षित प्रति अनुज्ञप्तिधारी के सम्बन्धित कार्यालयों में सामान्य कार्य-समय में जनता को निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवाएगा;
- (3) प्रत्येक नए उपभोक्ता को, और किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरोध प्राप्त होने पर, ऐसे मूल्य पर, उपभोक्ता अधिकार विवरण की अद्यतन प्रति उपलब्ध करवाएगा, जो उसके द्विप्रतिलिपिकरण की लागत से अधिक न हो ;

(घ) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कर्तव्य हेतु निष्पादन के मानको का, आयोग समय-समय पर यथानिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से पालन करेगा।

19. वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक, वितरण पद्धति प्रचालन मानक, सम्पूर्ण निष्पादन मानक.— (1) जब तक कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक और वितरण प्रणाली प्रचालन मानक आयोग द्वारा अनुमोदित न कर दिए जाएं, वितरण अनुज्ञप्तिधारी विद्यमान वितरण प्रणाली योजना, सुरक्षा मानकों और विद्यमान वितरण प्रणाली एवं प्रचालन मानकों का पालन ऐसे उपांतरणों के साथ करेगा जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण कोड के साथ वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानको के अनुसार अपनी वितरण प्रणाली योजना बनाएगा, प्रचालित करेगा और विकसित करेगा।

(3) (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा विशेष शर्तों में, या अन्यथा, निर्दिष्ट समय के भीतर, आयोग को अपनी वितरण प्रणाली के विद्यमान योजना और सुरक्षा मानक और प्रचालन मानक तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनाए अपनी वितरण प्रणाली से संयोजित उत्पादन क्षमता से सम्बन्धित विद्यमान योजना और सुरक्षा मानक व प्रचालन मानक प्रस्तुत करेगा। ऐसे विद्यमान मानक, आयोग द्वारा निर्दिष्ट उपांतरणों सहित, तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक आयोग नए मानक अनुमोदित न कर दें।

(ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा विशेष शर्तों में, या अन्यथा निर्दिष्ट समय के भीतर, आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड तथा अन्य व्यक्तियों, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, के परामर्श से, वितरण

अनुज्ञप्तिधारी की वितरण योजना और सुरक्षा मानक और वितरण प्रचालन मानक और इन विनियमों में अर्न्तविष्ट सामान्य शर्तों के अनुसार प्रचालन मानक के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रस्ताव आयोग के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा ;

(ग) इस विनियम के अनुसरण में वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत किए गए वितरण योजना और सुरक्षा मानक और वितरण प्रचालन मानक, और प्रचालन मानक उपांतरणों सहित, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, आयोग द्वारा यथानिर्देशित तारीखों से प्रभावी होंगे ।

(4) यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण योजना और सुरक्षा मानकों या वितरण प्रचालन मानकों के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने में अपरिहार्य घटना के कारण असफल रहता है, तो वह अपने दायित्वों को भंग करने का दोषी नहीं होगा । परन्तु यह कि वह तब जब वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथास्थिति वितरण योजना और सुरक्षा मानकों और वितरण प्रचालन मानकों, के पालन हेतु उचित प्रयत्न किए जा चुके हों ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, से परामर्श के पश्चात् ग्रिड कोड के प्रत्येक पुनर्विलोकन पर मानकों का पुनर्विलोकन करेगा । ऐसे किसी भी पुनर्विलोकन के उपरान्त वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को निम्न प्रेषित करेगा, नामतः —

(क) पुनरावलोकन के परिणाम पर एक रिपोर्ट; और

(ख) दस्तावेजों का पुनरीक्षण जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी (पुनर्विलोकन के परिणाम को ध्यान में रखते हुए) समय-समय पर, प्रस्तावित करता है; और

(ग) आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता, राज्य पारेषण उपयोगिता, प्रादेशिक विद्युत बोर्ड तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों, जैसे आयोग परामर्श प्रक्रिया के दौरान निर्देशित करे, से प्राप्त अभ्यावेदन या आपत्तियाँ जिनमें वे भी होंगी (जिन्हें वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने स्वीकार न किया हो) :

परन्तु यह कि आयोग, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा मानकों की समीक्षा और उनके निष्पादन के दायित्व से, उस सीमा तक मुक्त कर सकता है जिस तक इस शर्त के प्रयोजनार्थ वितरण अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा निर्देश जारी किए जाएं ।

(6) आयोग प्राप्त लिखित अभ्यावेदन और आपत्तियों के दृष्टिगत तथा इसके उपरान्त ऐसे परामर्श जिसे आयोग उचित समझता हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दिए गए निर्देशों के अनुसार मानकों का पुनर्विलोकन करने को कह सकता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट पुनरीक्षण को सम्यक् रूप से कार्यान्वित करेगा।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ती के तीन मास के भीतर, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के काम को प्रदर्शित करते हुए एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मानकों के निष्पादन को वितरण कोड, प्रदाय कोड, प्रदाय की शर्तों व अन्य कोड व आयोग के विनियमों की अनुपालना द्वारा भागतः मापा जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी, यदि आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए, आयोग द्वारा अनुमोदित रीति से रिपोर्ट की एक संक्षेपिका प्रकाशित करेगा।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रीति में, अपने अनुज्ञप्त करोबार को संचालित करेगा जिसे वह आयोग के, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, निर्दिष्ट किये गए के अनुसार उपभोक्ता द्वारा प्रदाय सेवाओं और विद्युत के दक्ष उपयोग के उन्नयन को सम्बन्ध में निष्पादन मानक प्राप्त करने हेतु युक्तियुक्त रूप में सर्वोत्तम समझता हो।

(9) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वार्षिक रूप से आयोग को उन जानकारीयों को देगा जिनके द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू निष्पादन मानकों और अन्य मानकों को पूरा करेगा।

20. उपभोक्ताओं को सार्वजनिक प्रकाश से जोड़ने का दायित्व.— (1) इस अधिनियम तथा इन विनियमों में अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए वितरण अनुज्ञप्तिधारी अपने प्रदाय क्षेत्र में किसी भी परिसर के स्वामी या अधिभोगी से आवेदन प्राप्त होने पर उन परिसरों को विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित आयोग के लागू विनियमों, निर्देशों और आदेशों के अनुसार विद्युत का प्रदाय उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से जोड़ेगा।

(2) जहां उप-विनियम (1) के अधीन वितरण मुख्यतार (मेन) बिछाया जा चुका हो तथा उन मुख्यतारों के माध्यमों से या उन में से किसी एक के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय प्रारम्भ हो चुका हो और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रदाय क्षेत्र के भीतर वितरण अनुज्ञप्तिधारी से किसी सार्वजनिक लैम्प के लिए कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिए प्रदाय की अपेक्षा की जाती हो, तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वहाँ तक जहाँ कि वह ऐसा करने के लिए किन्हीं अपरिहार्य घटनाक्रम होने से या तकनीकी अवरोधों द्वारा बाधित न हो, तब तक ऐसे सार्वजनिक लैम्पों के लिए उतनी मात्रा में ऊर्जा का प्रदाय जारी रखेगा जितनी की यथास्थिति राज्य सरकार

या स्थानीय प्राधिकारी, द्वारा अपेक्षा की जाए या राज्य सरकार या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी से निम्नलिखित अपेक्षा कर सकेंगे :—

(क) सार्वजनिक लैम्प के मुख्यतार और अन्य उपस्कर उपलब्ध कराना; और

(ख) उस प्रयोजन के लिए अवलम्ब का उपयोग, यदि कोई हो, जिसे ऊर्जा के प्रदाय के लिए उसके द्वारा पूर्व में खड़ा किया गया हो, या स्थापित किया गया हो ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत और आयोग द्वारा अनुमोदित प्रदाय तथा साथ में अधिनियम और आयोग के विनियमों के उपबन्धों के अनुसार सकर्मा को कार्यान्वित करने/विद्युत प्रदाय करने के लिए किन्हीं युक्तियुक्त प्रभारों को उद्ग्रहित कर सकेंगा ।

21. प्रदाय का दायित्व और विद्युत प्रदाय योजना मानक.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे समस्त कदम उठाएगा जो कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से जुड़े हुए समस्त उपभोक्ता निष्पादन मानकों और अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों और आयोग द्वारा जारी विनियमों और दिशा-निर्देशों के उपबन्धों के अनुसार विद्युत का सुरक्षित, मितव्ययी और विश्वसनीय प्रदाय प्राप्त करे ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 67 के उपबन्धों के अध्वधीन रहते हुए भूमि, अधोभूमि तथा सार्वजनिक प्रयोग हेतु मार्गों, गलियों, सार्वजनिक चौराहों और सार्वजनिक अधिपत्य की अन्य सम्पत्तियों के उपयोग व नदियों, पुलों, रेल, विद्युत व संचार लाइनों को, पार करने का हकदार होगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी :—

(क) आगामी 10 वर्षों के प्रत्येक वर्ष में प्रदाय क्षेत्र के भीतर ऊर्जा की वार्षिक माँग का पूर्वानुमान लगाएगा ;

(ख) समय-समय पर आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन के अनुसार आयोग को ऐसे पूर्वानुमान तैयार कर प्रस्तुत करेगा ;

(ग) राज्य के लिए ऊर्जा माँग पूर्वानुमान की तैयारी में पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य

पारेषण उपयोगिता और राज्य भार प्रेषण केन्द्र से सहयोग करेगा ; और

- (घ) आर्थिक वृद्धि दर, टैरिफ स्तरों तथा विद्युत माँगों में मूल्य – सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए, भार शोध (अनुसंधान) करेगा तथा राज्य के लिए अधिकतम तथा न्यूनतम भार वर्धन द्रव्य-योजना तैयार करेगा ।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी पूर्वगामी उप-विनियमों के अध्वधीन रहते हुए आयोग की सहमति से उत्पादन कम्पनियों, विद्युत व्यापारियों और अन्य से वितरण अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं की माँग की पूर्ति के लिए ऐसी मात्रा में, जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी समुचित समझे, विद्युत का क्रय करेगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के लागू होने के तीन मास या आयोग द्वारा अनुमत अन्य समय के भीतर, वितरण अनुज्ञप्ति के प्रचालन के सम्बन्ध में आने वाली आपातस्थितियों से निपटने हेतु आपात प्रबन्धन योजना बनाएगा और आयोग को मन्जूरी के लिए प्रस्तुत करेगा । इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ आपातस्थिति से अभिप्राय कोई ऐसे हालात और/या परिस्थिति से होगा जो मुख्यतः और प्रतिकूल रूप से :-

- (क) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के पूरे अथवा भागतः अनुज्ञप्त कारोबार के सुरक्षित, पर्याप्त और निरन्तर प्रचालन हेतु अनुज्ञप्तिधारी की क्षमता पर प्रभाव डाले; या
- (ख) किसी अन्य व्यक्ति, संयंत्र, या अन्य प्राणी, उपस्कर या सम्पत्ति की सुरक्षा को संकटापन्न करे ।

22. व्यय वसूली तथा प्रतिभूति माँगने की शक्ति.— (1) अधिनियम और इस निमित्त उसके अधीन बनाए गए नियमों व विनियमों के उपबन्धों के अनुसार वितरण अनुज्ञप्तिधारी को टैरिफ, प्रभार, फीस आदि वसूल करने और विद्युत प्रदाय या अन्य सेवाओं के लिए प्रतिभूति निक्षेप की अपेक्षा करने का हक होगा ।

23. मीटरिंग, बिलिंग, वसूली, ऊर्जा संपरीक्षा तथा क्षति.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, मीटर के माध्यम से विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित अधिनियम और आयोग के विनियमों, निर्देशों तथा आदेशों की सभी अपेक्षाओं का पालन करेगा ।

- (2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जब तक उपभोक्ता मीटर खरीदने का विकल्प नहीं करता

है, उपभोक्ता से मीटर के मूल्य की प्रतिभूति तथा उसके भाड़े पर देने के लिए करार करने की अपेक्षा कर सकता है।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा मन्जूर प्रत्याभूत मानकों में अधिकतम नियत समय के भीतर खराब तथा निष्क्रिय मीटर को इलैक्ट्रॉनिक मीटर से बदलेगा।

(4) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाई गई ऊर्जा के लिए उधार व्यवस्था को विलुप्त करने के लिए चरणबद्ध रीति से पूर्व संदाय मीटर व्यवस्था प्रारम्भ करेगा।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, राजस्व प्रशासन को सरल और कारगर बनाने हेतु समयबद्ध मीटर वाचन, बिलिंग, राजस्व वसूली तथा विच्छेदना (Disconnections) की प्रक्रिया का पुनर्विलोकन करेगा तथा उसे आयोग की मन्जूरी हेतु प्रस्तुत करेगा।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनिवार्य ऊर्जा संपरीक्षा कराएगा।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने, राजस्व बढ़ाने तथा पारेषण तथा वितरण क्षति कम करने के लिए अपने कारोबार की योजना बनाएगा और उसका प्रबन्धन करेगा।

(8) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, सर्वोत्तम प्रदाय/मांग संतुलन बनाने के लिए माँग प्रबन्धन करेगा।

24. संयोजन तथा प्रणाली का प्रयोग.— वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा खुली पहुँच के लिए विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार, अपनी प्रणाली में पर्याप्त वितरण क्षमता की उपलब्धता होने पर और उपभोक्ताओं द्वारा समस्त अनुज्ञात प्रभार, जिनमें वितरण प्रभार व जहाँ लागू हो अधिभार भी हैं, के सन्दाय करने को सहमत होने पर उपभोक्ताओं को अपनी वितरण प्रणाली तक अविभेदकारी खुली पहुँच प्रदान करने हेतु व्यवस्था करेगा।

25. सम्भावित राजस्व गणना और टैरिफ.— (1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि में,—

(क) विभिन्न उपभोक्ता वर्गों के लिए विश्वसनीय और सही लागत तथा व्यय के आधार आँकड़े बनाएगा, ताकि स्टेक-होल्डर, कुछ हद तक विनियामक निश्चयता से,

टैरिफ अवधारण हेतु विवेकपूर्ण आधार पाने के लिए इन लागतों तथा व्यय पर संकेद्रित कर सके;

- (ख) प्रदाय की सीमान्त लागत, जिसमें बोल्टा स्तर तथा उपभोक्ता वर्गों की अन्तरीय सीमान्त लागत भी सम्मिलित है, का अध्ययन करवाएगा;
- (ग) बोल्डताक्रम से परिसम्पत्ति, लागत तथा बिक्री की विस्तृत जानकारी देगा ताकि भविष्य में प्रति-सहायिकी ठीक-ठीक परिमित हो सके ।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम, आयोग के विनियमों, टैरिफ के नियमों व शर्तों व आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले अन्य मार्गदर्शन, आदेशों और निर्देशों के उपबन्धों के अनुसार प्रभारों, जिसे उसे प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किया गया है, से संभावित राजस्व की गणना करेगा ।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी संभावित राजस्व गणना और आयोग के टैरिफ अवधारण हेतु विनियमों में दिए गए निबन्धनों व शर्तों के अनुसार टैरिफ प्रस्ताव का आवेदन देगा ।

(4) जब तक विशेष शर्तों या आयोग द्वारा दिए गए किसी आदेश या निर्देश द्वारा अन्यथा उपबन्धित न किया गया हो, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रति वर्ष, 30 नवम्बर तक आयोग को—

- (क) अधिनियम और उसके अधीन आयोग द्वारा, समय-समय पर जारी, विनियमों, दिशा-निर्देशों और आदेशों के उपबन्धों के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्ष की संभावित संकलित राजस्व और सेवा लागत (जिसमें लागत वित्तपोषण और अकिवटि पर इसकी सम्भावित आय सम्मिलित है) का विस्तृत विवरण देगा;
- (ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित वार्षिक निवेश योजना के विवरण और जिसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी, आयोग द्वारा पहले से ही ऐसे निवेश हेतु अनुमोदित योजनाओं, यदि कोई हों, के उचित संदर्भ में, आगामी वित्तीय वर्ष में राजस्व आवश्यकता के अधीन लाने का इच्छुक हो, का विनिर्दिष्ट निवेश योजना विवरण देगा ;

वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को अपने प्रत्येक अनुज्ञप्त और अन्य कारोबार के बारे में इसमें इससे पूर्व संदर्भित कथन तथा निवेश योजना का विवरण

अलग-अलग देगा ।

(5) वितरण अनुज्ञप्तिधारी, संभावित राजस्व गणना या अन्य किसी ऐसे समय और आवर्तन में आयोग जैसे विशेषतः अनुज्ञात करे, टैरिफ प्रस्तावों और आयोग द्वारा अनुमोदित विद्यमान टैरिफ में संशोधन, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व आवश्यकताओं से मेल खाता हो, का आवेदन देगा ।

(6) वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ से वसूल की जाने वाली राशि वह राशि होगी जिसे आयोग अधिनियम के और आयोग के विनियमों के उपबन्धों के अनुसार अनुमोदित करे ।

(7) वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग को, अधिनियम तथा आयोग के विनियमों व निर्देशों के अनुसार, टैरिफ में संशोधन हेतु आवेदन दे सकता है ।

26. उपभोक्ताओं को सहायिकी का उपबन्ध.— यदि राज्य सरकार आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को सहायिकी मन्जूर करने की अपेक्षा करती है, तो राज्य सरकार ऐसे किसी निदेश के होते हुए, भी जो अधिनियम की धारा 108 के अन्तर्गत किसी को भी दिया जाए अग्रिम में और ऐसी रीति से जैसा आयोग निर्दिष्ट करे, सहायिकी मन्जूरी से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिकर का संदाय ऐसी रीति में, जैसे आयोग निर्दिष्ट करे, करेगी :

परन्तु राज्य सरकार का ऐसा कोई निदेश प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि संदाय अधिनियम और आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार नहीं किया गया है और अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से आयोग द्वारा, इस संबन्ध में, जारी किए गए आदेशों की तारीख से आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ के अनुसार वसूली करेगा ।

27. अनुज्ञप्तिधारी की परिसर में प्रवेश करने और उपस्करों व अन्य उपकरणों को हटाने की शक्ति.— (1) अधिनियम की धारा 163 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी और कोई भी सम्यक्तः प्राधिकृत व्यक्ति, युक्तियुक्त समय पर और अधिभोगी को अपने आशय से सूचित करके निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये किसी भी परिसर, जिसको विद्युत प्रदाय किया गया है या जिसके ऊपर से विधिपूर्ण विद्युत की लाईनें बिछाई और संकर्म स्थापित किये गए हैं, में प्रवेश कर सकेगा,—

(क) विद्युत प्रदाय लाईनों, मीटरों, तथा अनुज्ञप्तिधारी के संकर्म के बदलाव, मुरम्मत करने, परीक्षण व निरीक्षण के लिए; या

(ख) प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा अभिनिश्चित करने के लिए; या

(ग) जहां विद्युत प्रदाय की अब आवश्यकता नहीं है वहां ऐसी लाईनों, फिटिंग, संकर्मों को हटाने के लिए ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी और उसका प्राधिकृत व्यक्ति कार्यापालक मैजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए किए गए विशेष आदेश पर अधिभोगी को 24 घंटे से अन्यून की सूचना देने के प्रश्चात् उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकेगा ।

(3) परिसर के अधिभोगी द्वारा प्रवेश की अनुमति न देने पर, अनुज्ञप्तिधारी जब तक प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती, विद्युत प्रदाय उस समय तक जब तक ऐसा इनकार जारी रहता है, काट सकता है ।

28. विद्युत काटना.— (1) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय काटने से पूर्व, पूरे 15 दिन की स्पष्ट लिखित सूचना देगा ।

(2) अनुज्ञप्तिधारी विद्युत प्रदाय बन्द नहीं करेगा, यदि कोई व्यक्ति विरोध के अधीन,—

(क) उससे दावा की गई राशि के बराबर रकम का; या

(ख) पूर्ववर्ती छः मास के दौरान उसके द्वारा संदत्त विद्युत के लिए औसत प्रभार के आधार पर संगठित प्रत्येक मास के लिए उससे शोध्य विद्युत प्रभारों का,

इन में से जो भी कम हो, उसके और अनुज्ञप्तिधारी के बीच किसी विवाद का निपटारा होने तक, निक्षेप कर देता है ।

(3) अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत प्रभारों की ऐसी राशि को बकाया के रूप में दो वर्ष की अवधि तक लगातार वसूलीय दर्शाना होगा ।

(4) अनुज्ञप्तिधारी को.—

(क) विद्युत प्रदाय के स्रोत बिन्दु पर मीटर द्वारा मापने;

(ख) राजस्व उगाही;

- (ग) आयोग द्वारा यथानुमोदित उधार नियन्त्रण प्रक्रिया का कार्यान्वयन;
- (घ) चोरी के लिए अभियोजन;
- (ङ) मीटर को बिगाड़ने से रोकने;
- (च) विद्युत उपयोजन रोकने ;
- (छ) विद्युत के अनाधिकृत उपयोग को रोकने; और
- (ज) वितरण या खुदरा प्रदाय को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के सभी मामलों में;

अधिनियम की धारा 126, 127, 135-140 के अनुसरण में उचित कार्यवाही करने की शक्ति और अधिकार होगा ।

29. विविध.—(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी (वैज्ञानिक व्यवस्थित) अभियन्त्रिकी संसाधन प्रबन्धन तथा वर्धित उत्पादिता हेतु प्रबन्धकीय कूटरचना (रणनीति) तथा मानव संसाधन, पद्धति तथा नैपुण्य में सुधार लाकर तथा उसका अद्यतन करके अपनी विद्यमान जनशक्ति की दक्षता को युक्तिसंगत बनाएगा ।

(2) इन विनियमों की और उनकी शर्तों के बारे में व्याख्या से सम्बन्धित उठने वाले सभी विवादक आयोग द्वारा अवधारित किए जाएंगे और ऐसे विवादकों पर आयोग का विनिश्चय केवल अधिनियम की धारा 111 के अपील करने के अधिकार के अध्यक्षीन अन्तिम होगा ।

(3) आयोग वितरण अनुज्ञप्ति मन्जूर करते समय, या तो अनुज्ञप्ति मन्जूर करने वाले आदेश में या किसी विनिर्दिष्ट वितरण अनुज्ञप्तिधारी पर लागू होने वाली विशेष शर्तों द्वारा इन विनियमों के किसी भी लागू उपबन्ध का अधित्यजन या उपान्तरण कर सकता है ।

30. समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों पर लागू उपबन्ध.—अधिनियम लागू होने पर वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सभी आवेदकों, और अधिनियम की धारा 14 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पाँचवे परन्तुकों के अधीन सभी समझे गए अनुज्ञप्तिधारियों, पर एतद्वारा दी गई सामान्य शर्तें लागू होंगी ।

31. कठिनाईयाँ दूर करना.—(1) आयोग, अधिनियम के अध्यक्षीन रहते हुए, समय-समय पर, इन विनियमों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में जिसके लिए आयोग को इन विनियमों द्वारा और उनसे सम्बन्धित, प्रासंगिक या आनुषंगिक मामलों में निर्देश देने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश अथवा पद्धति निर्देश दे सकता है ।

(2) यदि इन विनियमों के किसी भी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है, तो आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा वितरण अनुज्ञापिधारी को ऐसी समुचित कार्रवाई करने या करने को मानने के लिए कह सकता है, जो आयोग की राय में कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक या समीचीन लगे ।

(3) इस विनियम के अधीन कोई भी आदेश इन विनियमों के लागू होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के अवसान पर नहीं किया जाएगा और इन विनियमों के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन होगा और उसके जारी होने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

32. निरसन और अपवाद.— (1) इन विनियमों में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 या विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 या अन्य किसी विधि के अधीन वितरण अनुज्ञापि के लिए जारी किन्हीं सामान्य या विशेष शर्तों को, जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व लागू हों, एतद्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, वितरण अनुज्ञापि की निरस्त सामान्य या विशेष शर्तों के अधीन की गई कोई कार्रवाई या अभिप्रेत कार्रवाई, जब तक इन विनियमों के उपबन्धों से अनसंगत न हो, के इन विनियमों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन किया गया समझा जाएगा ।

(3) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व जारी वितरण अनुज्ञापि की विशेष शर्तें और निर्देश (जिसमें विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अधीन सुनवाई के दौरान टैरिफ आदेश, 2001-02 के अध्याय 7 में उल्लिखित निर्देश सम्मिलित हैं), जो इन विनियमों के उपबन्धों से अनसंगत नहीं हैं, उस अवधि तक लागू रहेंगे जब तक के लिए ऐसी सामान्य या विशेष शर्तें या निर्देश जारी किए गए थे ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/—
सचिव ।